कमल संदेश

ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-

त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798

Qku (dk-) : +91(11) 23381428

QDl : +91(11) 23387887

पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय-सूची

आवरण कथा : भाजपा अध्यक्ष का प्रवास

उत्तर प्रदेश 6

असम 7

लेख

हैदराबाद में 'ऑपरेशन पोलो'
– **लालकृष्ण आडवाणी** 8

सीबीआई कामकाज में जीओएम की सिफारिशें मात्र-एक छल
– **अरुण जेटली** 12

पंथनिरपेक्षता के नाम पर भेदभाव
–**बलबीर पुंज** 18

बना रहना चाहता है 'पिंजरे में बन्द तोता' संप्रग का सहयोगी
–**अम्बा चरण वशिष्ठ** 21

अर्थव्यवस्था की डूबती नाव
–**लार्ड मेघनाद देसाई** 23

सामूहिक चर्चा

श्रीमती मीनाक्षी लेखी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा 15

अन्य

डॉ. मुकर्जी बलिदान दिवस पर विशेष चर्चा 14

भाजपा, महिला मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक 25

जन्मदिवस (23 जुलाई) पर विशेष

शहीद शिरोमणि चन्द्रशेखर आजाद / **विकास आनन्द** 30

प्रदेशों से

राजस्थान (26), हिमाचल प्रदेश (27), हरियाणा (28), बिहार (29), आन्ध्र प्रदेश (22)

मुख पृष्ठ : ***गुवाहाटी में एक रैली को सम्बोधित करते भाजपाध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह***

ऐतिहासिक चित्र

भारतीय जनसंघ 'युवक सम्मेलन' बम्बई 1970

बोध कथा

बापू का गुस्सा

उन दिनों गांधीजी चंपारण में थे। एक सुबह वह अपनी कुटिया के बाहर बैठकर चरखा कात रहे थे। उनके सामने दो बच्चे खेलते-खेलते एकाएक लड़ने लगे। वे दोनों इतने उत्तेजित हो गए कि एक-दूसरे को भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे।

उन छोटे बच्चों के मुंह से गालियां सुनकर गांधीजी को बेहद अफसोस हुआ। उन्होंने आसपास के लोगों से उन दोनों के मां-बाप के बारे में पता किया। फिर उन्होंने एक दिन उनके मां-पिता को बुला भेजा। वे लोग यह जानकर आश्चर्यचकित भी हुए और खुश भी कि उन्हें बापू ने बुलाया है। वे गांधीजी के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। गांधीजी ने उन्हें डांटना शुरू कर दिया।

बच्चों के मां-बाप घबराए। वे सिर झुकाए, खामोशी से सब कुछ सुनते रहे। लेकिन एक बच्चे के पिता से रहा नहीं गया। उसने पूछा- बापू क्षमा करें। हम समझ नहीं पा रहे कि हमसे क्या गलती हो गई है? गांधीजी ने स्थिति स्पष्ट की- सुनो। तुम लोगों के बच्चे यहां खेल रहे थे। अचानक उनमें झगड़ा हो गया और वे एक-दूसरे को गाली देने लगे। इस पर उस व्यक्ति ने कहा- लेकिन इसके लिए आपने हमें क्यों बुलाया? आप उन्हें बुलाकर डांट देते। आपको उन्हें डांटने का पूरा अधिकार है।

गांधीजी बोले- देखो। मैं उन्हें डांट सकता था। पर तब न जब वे दोषी होते। ये गालियां उन्होंने तुम लोगों से ही सीखी होंगी। या कहीं और किसी से भी सीखी हो तो तुम लोगों ने उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं की। इसलिए दोषी तुम लोग हुए। डांट तुम्हें पड़नी चाहिए। यह सुनकर बच्चों के अभिभावकों ने सिर झुका लिया।

संकलन : मुकेश शर्मा
(नवभारत टाइम्स)

व्यंग्य चित्र

प्रिय पाठकगण

कमल संदेश (पाक्षिक) का अंक आपको नियमित मिल रहा होगा। यदि किन्हीं कारणवश आपको अंक प्राप्त न हो रहा हो तो आप अपने प्रदेश कार्यालय को या हमें अवश्य सूचित करें।

-सम्पादक

जन-जन को उठाना होगा गांडीव

सरकार जब षड्यंत्र करने लगे तो लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? यूपीए सरकार, जिसे कांग्रेस की सरकार कहना उचित होगा, अब सरकार चलाने के बजाए वह अगली सरकार बनाने के लिए एक नहीं अनेक षड्यंत्रों का जाल बिछाने में लगी है। जबकि जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि कब चुनाव हो और कांग्रेस नीत यूपीए से मुक्ति मिले।

यूपीए सरकार महंगाई से आम जन को मौत परोस रही है। दाल-रोटी खतरे में। बच्चों की पढ़ाई खटाई में। भविष्य के लिए एक छोटे मकान का सपना पूरी होने की कोई सम्भावना नहीं। खेती फायदे का सौदा नहीं। मनरेगा के नाम पर धांधली। उद्योग-धंधों के नाम पर कुटीर उद्योगों पर तालाबंदी, निवेश के नाम पर लूट, कालेधन का जोर। पसीने की कमाई कमजोर। बेरोजगारों की संख्या आबादी के अनुपात से बढ़ रही है। गांवों से पलायन जारी। चालीस फीसदी किसान किसानी छोड़ चुके हैं। कहने को देश कृषि प्रधान पर, देश के गांव खतरे में। बिजली के नाम पर अंधेरा। सिंचाई के नाम पर आधी अधूरी परियोजनाएं। पानी के नाम पर सूखे तालाब और सूखे कुएं। विद्यार्थी, शिक्षक और स्कूल में कोई समानुपात नहीं। विद्यार्थी है तो स्कूल नहीं, स्कूल है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो स्कूल की इमारत नहीं। अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों की हालत जर्जर। न चिकित्सक का पता, न दवाई का। गांव के गांव उजड़ रहे हैं पर सरकारी दस्तावेजों में गांव के गांव आबाद हो रहे हैं।

भारत की इससे बड़ी और दुर्दशा क्या होगी कि यहां के प्रधानमंत्री ने कभी किसी गांव का पिछले नौ वर्षों में दौरा तक नहीं किया। सड़कों पर नजर दौड़ायेंगे तो लगता है कि यूपीए सरकार ने निर्णय लिया है कि सड़क बनाना जैसे गुनाह हो गया हो। नेशनल हाईवे पर कछुए की चाल से काम हो रहा है।

यूपीए का देश में अधोसंरचना की ओर कोई ध्यान नहीं, उलटे, एनडीए ने जो अधोसंरचना की ओर ध्यान दिया था या स्थापित किया था उसे भी ठप कर दिया गया। देश की सीमाएं, संविधान और सैनिक असुरक्षित। विदेश नीति और कूटनीति अत्यंत विफल। भारत की स्थापित और बढ़ रही साख को गहरा आघात इन नौ वर्षों में लगा है। हम सकारात्मक दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं तो भी घोटालों के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। यूपीए सरकार के काबिना मंत्रियों की साख दो कौड़ी की हो चुकी है। एक दिन में दो-दो केन्द्रीय मंत्रियों को संदिग्ध आरोपों में हटाने की घटना ने यूपीए सरकार का सिर शर्म से झुका दिया है। न नीति, न सिद्धांत से कोई वास्ता सिर्फ कुर्सी की सुरक्षा में जुटी यूपीए विपक्षियों को फंसाने और उन्हें सत्ता प्रभाव से त्रस्त करने में जुटी हुई है।

सीबीआई, आयकर, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, और आईबी के साथ-साथ सभी केन्द्रीय संरचनाओं का दुरूपयोग करने में यूपीए सरकार महारत हासिल कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान कांग्रेसनीत यूपीए सरकार के खिलाफ जितने निर्देश और आदेश दिए हैं, पूर्व में किसी सरकार की ऐसी कभी दुर्दशा नहीं हुई। 'सरकार' की साख मिटाने का काम राजनीति और राजनेताओं के प्रति अनास्था पैदा करने का काम गत नौ वर्षों में जितना यूपीए के कार्यकाल में हुआ उतना पूर्व की किसी सरकार में नहीं हुआ।

आर्थिक मोर्चे पर विफलता, भ्रष्टाचार के मोर्चे पर अभूतपूर्व सफलता, यही है यूपीए की कार्यकुशलता। आम जन से निवाला छीन लिया, देश का दीवाला निकाल दिया और घोटाले कर-करके कांग्रेसियों ने अपने को मालामाल कर लिया। जिस ओर से और जिस नजर से, साक्षेप या निरपेक्ष जिस भी भाव से देखें तो लगता है कि यूपीए सरकार ने भारत के साथ धोखा ही धोखा किया है। 'वोट' किस नाम पर मांगे थे और वोट मिलने के बाद काम के बदले राज में नए-नए करनामे होते रहे। समय आ गया है, जब जनता को किसी की बातों में न आते हुए उसे गांडीव उठाना होगा और लोकतंत्र के हितार्थ उस यूपीए सरकार का वध करना होगा। तिरंगे की साख को रोज बट्टा लग रहा है। हमें अपनी मानसिकता के साथ-साथ देश की मानसिकता बदलने के लिए राष्ट्रीय कर्त्तव्य का दायित्व निर्वाह करना होगा। ■

कांग्रेसमुक्त भारत निर्माण हेतु सभी विपक्षी दल आगे आएं : राजनाथ सिंह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने गत 26 से 28 जून 2013 तक लखनऊ के अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान उत्तराखंड में आयी आपदा हेतु राहत सामग्री रवाना करने के साथ ही राजधानी में प्रदेश इकाई द्वारा आयोजित कई बैठकों और कार्यक्रमों में भाग लिया। इस प्रवास के दौरान कई सामाजिक व व्यापारिक संगठनों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला। प्रदेश भर से काफी बड़ी संख्या में आये कार्यकर्ताओं ने भी मुलाकात कर उनसे विचार-विमर्श किया। 27 जून को पत्रकार वार्ता के दौरान श्री सिंह ने नौ वर्षों से केन्द्र में सत्तारूढ़ यूपीए सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कांग्रेसमुक्त भारत निर्माण का आह्वान किया।

बाह्य सुरक्षा अथवा कूटनीतिक मोर्चे जैसे प्रत्येक प्रश्न पर यूपीए सरकार असफल साबित हुई। उनका कहना था कि देश संकट में है इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। केन्द्र का राजकोष खाली है। रुपये की कीमत लगातार घटती जा रही है। आज डॉलर की कीमत 60 रूपए से ऊपर पहुंच गयी है। यूपीए के पूरे नौ साल का कार्यकाल घोटालों और भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। श्री सिंह ने एनडीए सरकार के कार्यकाल की यूपीए की तुलना करते हुए श्री सिंह ने कहा कि एनडीए शासन काल में करीब 6 करोड़ 20 लाख रोजगार उपलब्ध कराए गए जबकि यूपीए सरकार द्वारा 5 वर्ष में मात्र 27 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किए। उनका कहना था कि माओवाद व नक्सलवाद कांग्रेस शासन काल में जड़ जमा चुका है। भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति करनेवाली कांग्रेस अब अपना एजेंडा बदलकर धर्मनिरपेक्षता बनाम साम्प्रदायिकता बहस छेड़ना चाहती है। दूसरों को धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट देने वाली कांग्रेस स्वयं साम्प्रदायिक पार्टी है।

26 जून को उत्तराखंड आपात पीड़ितों के लिए राहत सामग्री की खेप रवाना करने के पूर्व पत्रकारों से बातचीत में भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि वह उत्तराखंड की आपदा में फंसे 15 हजार गुजरातियों को बचा ले गये। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए ऐसा प्रचार कराकर मोदी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मोदी उत्तराखंड में पीड़ित लोगों से संवेदना जताने वहां चल रहे राहत कार्य की जानकारी लेने गए थे। भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई है। सबको मिलकर इससे निपटना है। उन्होंने बताया कि पार्टी विधायकों व सांसदों ने 1 माह का वेतन उत्तराखंड राहत में देने का निर्णय लिया है। लखनऊ भाजपा कार्यालय में आपदा दानपत्र में भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री अमित शाह सहित अनेक पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सहयोग राशि दिया। कार्यक्रम के अंत में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय से आधा दर्जन ट्रकों से राहत सामग्री को हाथ जोड़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तराखंड के लिए रवाना किया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री राजनाथ सिंह पहली बार प्रदेश की राजधानी लखनऊ गये थे लेकिन उत्तराखंड में आयी प्रकृतिक आपदा के कारण कार्यकर्ताओं ने हवाई अड्डे से प्रांतीय

मुख्यालय तक कहीं भी न स्वागत किया और न नारा लगाया। कहीं भी पार्टी का बैनर-पोस्टर नहीं लगा था। फूल-माला से भी उनका स्वागत इस आपदा को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया।

लखनऊ में प्रदेश पदाधिकारियों और प्रमुख नेताओं से उसी दिन सायं बैठक संपन्न हुई। प्रदेश के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठन को मजबूत करने के लिए लोगों से सुझाव मांगा और अंत में मार्गदर्शन करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में 50 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य बताया। युवा व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल श्री अशोक मोतियानी के नेतृत्व में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह से मिला। प्रदेश की कानून व्यवस्था व बिजली संकट जैसी समस्यायें गिनाने के बाद व्यापारियों ने एफडीआई को भारत से खदेड़ने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों का कहना था कि नरेन्द्र मोदी को यू.पी. से चुनाव लड़ना देशहित में रहेगा।

लखनऊ प्रवास के दूसरे दिन प्रदेश भर से आये भारी संख्या में कार्यकर्ताओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले। इसके बाद प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नौ वर्षों तक केन्द्र की यूपीए सरकार का कार्यकाल विफल रहा है। हर मोर्चे पर कांग्रेस सरकार को विफल बताते हुए श्री सिंह ने कांग्रेस मुक्त भारत निर्माण का आह्वान किया।■

(डा. अनुपम आलोक की रिपोर्ट)

"भारत को यथार्थवादी प्रधानमंत्री चाहिए"

देश के आर्थिक हालात के लिए केंद्र की संप्रग सरकार की आलोचना करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने 3 जुलाई को कहा कि एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री होने के बावजूद देश की वित्तीय सेहत बिगड़ रही है। श्री सिंह ने कहा, ''देश की सत्ता 'मौनपुरुष' के बजाय 'लौहपुरुष' के हाथों में होनी चाहिए। जो व्यक्ति कभी नहीं बोलता, उसे देश का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए।'' जनवरी में भाजपा का अध्यक्ष बनने के बाद असम के अपने पहले दौरे पर गए श्री राजनाथ सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित करते हुए कहा, ''देश को अर्थशास्त्री नहीं बल्कि यथार्थवादी प्रधानमंत्री चाहिए।'' देश की आर्थिक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि राजग सरकार में महंगाई नियंत्रण में थी। लेकिन अब हर चीज महंगी हो रही है। राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा बढ़ रहा है। भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि रुपए की कीमत घटने के पीछे कांग्रेस की सुनियोजित साजिश है क्योंकि पार्टी के नेता अब स्विस बैंकों में जमा काले धन को वापस ला रहे हैं। सभी समस्याओं के लिए कांग्रेस सरकार की खराब आर्थिक योजना और उसका भ्रष्टाचार जिम्मेदार हैं।

श्री सिंह ने असम से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को असम में बांग्लादेशियों के अवैध प्रवेश के कारण कथित तौर पर क्रमिक और गंभीर जनसांख्यिकीय बदलाव के प्रति आगाह करते हुए केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि पड़ोसी देश से इस घुसपैठ को रोकने के लिए बातचीत की पहल की जाए।

श्री राजनाथ सिंह ने रैली में कहा, ''मनमोहन सिंह जी कृपया बोलिए और कुछ दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाइए। आपने नौ साल तक देश पर शासन किया है। कृपया इस मुद्दे (बांग्लादेशियों के अवैध प्रवेश के विषय) को बांग्लादेश के साथ उठाइए क्योंकि इससे पूरे पूर्वोत्तर में गंभीर जनसांख्यिकीय बदलाव होने वाले हैं।'' उन्होंने कहा कि देश को अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए लेकिन अवैध घुसपैठ नहीं होने देनी चाहिए। सभा में भाजपा उपाध्यक्ष और प्रदेश के पार्टी मामलों के प्रभारी श्री एस एस अहलूवालिया भी उपस्थित थे।

श्री अहलूवालिया ने कहा कि गुवाहाटी नगर निगम के हाल ही में संपन्न हुए चुनावों के नतीजों में सत्तारूढ़ कांग्रेस के बाद भाजपा का दूसरे नंबर पर आना पार्टी की प्रदेश में बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। ■

हैदराबाद में 'ऑपरेशन पोलो'

लालकृष्ण आडवाणी

मेरे पिछले दो ब्लॉग मुख्यतया जम्मू एवं कश्मीर और डा. श्यामा प्रसाद मुकर्जी के बारे में थे। जिन्हें देश ने 'राष्ट्रीय एकीकरण के लिए स्वतंत्र भारत के पहले शहीद' के रुप में सराहा। इन दोनों के लिए मुझे वी. शंकर द्वारा लिखित वल्लभभाई पटेल की जीवनी-'माय रेमिनीसेंसेज ऑफ सरदार पटेल' पर काफी आश्रित होना पड़ा।

सरदार पटेल पर राजमोहन गांधी की जीवनी में लिखा है: "यद्यपि शंकर की सेवाएं बहुमूल्य थीं, परन्तु ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका वपल पनगुन्नी मेनन ने निभाई''।

सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत के गृहमंत्री के रूप में अपने मंत्रालय में एक 'स्टेट्स डिपार्टमेंट' का गठन किया जिस पर देश की 564 देसी रियासतों को एक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सरदार पटेल ने वी.पी. मेनन को स्टेट्स डिपार्टमेंट का सचिव नामांकित किया। जब भारत पर ब्रिटिश शासन था तब ये देसी रियासतें देश का लगभग आधा क्षेत्र बनती थीं।

दिसम्बर, 2000 में नई दिल्ली में श्री वी.पी. मेनन की स्मृति में सम्पन्न एक कार्यक्रम में लीला ग्रुप ऑफ होटल्स के प्रमुख कैप्टन सी पी कृष्णानायर ने स्वर्गीय मेनन की बहुमूल्य पुस्तकों का एक सेट मुझे भेंट किया था, इन पुस्तकों के बारे में माना जाता है कि वीपी ने यह स्वयं सरदार पटेल की तरफ से लिखीं : पहली का शीर्षक है "दि ट्रांसफर ऑफ पॉवर इन इण्डिया'' और दूसरी का "इंटीग्रेशन ऑफ दि इण्डियन स्टेट्स''। दूसरी वाली वास्तव में एक अद्भुत और स्वतंत्र भारत के पहले गृहमंत्री की महानतम उपलब्धि की अत्यन्त अधिकृत गाथा है।

महत्वपूर्ण रियासतों में से चार ने भारत में विलयीकरण के प्रति अपनी अनिच्छा प्रदर्शित की थी। इनमें हैदराबाद, जम्मू एवं कश्मीर, भोपाल और ट्रावनकोर थे। इनमें से हैदराबाद एकमात्र ऐसा राज्य था जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार को बल प्रयोग करने हेतु बाध्य होना पड़ा।

वी.पी. मेनन की पुस्तक में 87 पृष्ठों में फैले तीन अध्याय पूरी तरह से हैदराबाद पर केंद्रित हैं: यदि मैं संक्षेप में इसे समेटूं तो वीपी के स्वयं के शब्दों में, पण्डित नेहरु की हिचक के बावजूद क्यों सरदार पटेल ने निजाम के विरुद्ध सेना का उपयोग किया, तो वीपी लिखते हैं:

"स्टैन्ड्स्टल एग्रीमेंट (जिसे निजाम ने नई दिल्ली के साथ किया था) के अनुच्छेद II के अनुसार भारत सरकार ने के.एम. मुंशी को अपना एजेंट-जनरल नियुक्त किया। मैं तब तक मुंशी को अच्छी तरह से नहीं जानता था। लेकिन 1937 से 1939 में बॉम्बे के गृहमंत्री के रुप में उनके द्वारा साम्प्रदायिक स्थिति का सामना करने के तरीके से मैं विशेष रूप से प्रभावित था। जब हमने हैदराबाद सरकार को मुंशी की नियुक्ति के बारे में सूचित किया तो निजाम ने कुछ निश्चित शर्तें रखीं। सबसे पहले वह चाहते थे कि मुंशी व्यापार एजेंट से ज्यादा कुछ नहीं होने चाहिएं। मैंने लाइक अली (जिसे निजाम ने कासिम रिजवी की सलाह पर अपनी एक्जीक्यूटिव कांउसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया था) का ध्यान समझौते के अनुच्छेद II की ओर दिलाया जिसके तहत एजेंट-जनरल के काम निश्चित रुप से व्यापार तक सीमित नहीं थे।

एक छोटा परन्तु फिर भी महत्वपूर्ण विवाद मुंशी को हैदराबाद में रहने की सुविधा देने पर उत्पन्न हुआ निजाम ने यहां तक कि जब तक कहीं और आवास नहीं मिल जाता तब तक अस्थायी रुप से भी कोई आवास देने से मना कर दिया। अतंतोगत्वा, भारतीय सेना के दो भवन मुंशी और उनके स्टाफ के लिए उपलब्ध कराए गए।

इससे पहले कि स्टैन्ड्स्टल एग्रीमेंट

की स्याही सूखती, निजाम सरकार ने एक के बाद एक, दो अध्यादेश तुरंत जारी किए।

पहले में हैदराबाद से भारत को निर्यात किए जाने वाली बहुमूल्य धातुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरे में राज्य में भारतीय करेंसी के चलन को अवैध करार दे दिया गया।

25 दिसम्बर, 1947 को मैंने हैदराबाद सरकार को लिख कर यह बताया कि थे दोनों अध्यादेश स्टैण्डस्टील एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार को यह सूचना मिली कि हैदराबाद सरकार ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए का कर्जा भारत सरकार की प्रतिभूति की समतुल्य कीमत में दे दिया है।

यही काफी नहीं था। हैदराबाद की सरकार ने हमें अधिकृत रूप से सूचित किया कि उनकी मंशा अनेक विदेशी देशों में एजेंट नियुक्त करने की है। उन्होंने बिना भारत सरकार को सूचित किए पहले ही एक जनसम्पर्क अधिकारी कराची में नियुक्त कर दिया था।

इसके बाद विचार-विमर्श हुआ। मैंने जोर दिया कि हैदराबाद सरकार को विवादों में आए दोनों अध्यादेशों को वापस लेना चाहिए और पाकिस्तान सरकार से 20 करोड़ रुपए का कर्ज वापस देने के लिए कहना चाहिए। रजाकरों की गतिविधियों का संदर्भ देते हुए मैंने कहा कि उनके द्वारा हैदराबाद में उत्पन्न की गई स्थिति पर भारत सरकार ने गंभीर रुख लिया है। भारत सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि हैदराबाद की सरकार द्वारा इस प्रतिक्रियावादी और साम्प्रदायिक संगठन को हर तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मद्रास सरकार से भी इन रजाकरों द्वारा उनकी सीमा पर की जा रही गतिविधियों सम्बन्धी बेचैन करने वाली रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं।

इस बीच निजाम की एक्जीक्यूटिव कांऊसिल के अध्यक्ष लाइक अली दिल्ली आए और सरदार से मिले। सरदार ने उन्हें दृढ़ता से बताया कि भारत और हैदराबाद में संतोषजनक समझ की पहली अनिवार्यता है कि राज्य में आंतरिक निपटान होना चाहिए और उनसे इस दिशा में कार्य करने का अनुरोध किया। 30 जनवरी की शाम गांधीजी की हत्या के चलते वार्तालाप पूरा नहीं हो सका। लाइक अली और हैदराबाद प्रतिनिधिमण्डल तत्काल हैदराबाद लौट गया।

लार्ड माऊंटबेटन ने अपना निजी मत दिया कि यदि निजाम एक जिम्मेदार सरकार बनाने का अपना इरादा घोषित करते हैं तो दुनिया की नजरों में हैदराबाद की स्थिति और मजबूत हो जाएगी तथा इससे निजाम और उसके उत्तराधिकारियों के राज्य का संवैधानिक शासन सदैव के बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यदि सही समय गंवा दिया या यदि समय बीत गया, तो इसकी संभावना है कि निजाम अपना सिंहासन मात्र घटनाक्रम से बाध्य होकर गंवा देगा।

के.एम. मुंशी को अत्यन्त नाजुक और कठिन भूमिका निभानी थी। जबकि भारत सरकार और दिल्ली में निजाम के एजेंट-जनरल (नवाब जेन यार जंग) के सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण थे, उधर हैदराबाद की सरकार मुंशी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही थी और उसके उनके साथ सम्बन्ध एकदम तनावपूर्ण थे। उनके प्रति हैदराबाद सरकार के संदेह के चलते एक तरह से वह अपने ही घर में कैदी जैसे थे।

इस बीच, हैदराबाद सरकार ने मानी गई एक बात भी लागू नहीं की। लाइक अली द्वारा किए गए वायदे के बावजूद पाकिस्तान से कर्जा वापस लेने सम्बन्धी कोई घोषणा नहीं की गई, करेंसी अध्यादेश को नहीं सुधारा गया, जबकि बहुमूल्य धातु और तिलहन के निर्यात पर पाबंदी जारी रही। लाइक अली द्वारा किए गए वायदे के अनुसार निजाम की एक्जीक्यूटिव काऊंसिल के पुनर्गठन की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। रजाकरों पर प्रतिबंध लगाना तो दूर उल्टे वे असहनीय सिरदर्द बन रहे थे। सीमाओं पर छापामारी रूकने के कोई लक्षण नहीं थे। अब तक हम अपनी बातों को हैदराबाद सरकार के सामने अनौपचारिक रूप से उठा रहे थे। लेकिन अब भारत सरकार ने तय किया कि स्टैन्डिस्टल एग्रीमेंट के उल्लंघन की बातें अधिकारिक रूप से उनके संज्ञान में लाई जाए। तद्नुसार, 23 मार्च को मैंने निजाम की एक्जीक्यूटिव काऊंसिल के अध्यक्ष को सम्बोधित एक पत्र मुंशी को भेजा ताकि वह निजी रूप से इसे लाइक अली को दे सकें।

रजाकरों के समर्थन से हैदराबाद में सत्तारूढ़ गिरोह अब आक्रामक मूड में

निजाम की एक्जीक्यूटिव कांऊसिल के अध्यक्ष लाइक अली दिल्ली आए और सरदार से मिले। सरदार ने उन्हें दृढ़ता से बताया कि भारत और हैदराबाद में संतोषजनक समझ की पहली अनिवार्यता है कि राज्य में आंतरिक निपटान होना चाहिए और उनसे इस दिशा में कार्य करने का अनुरोध किया। 30 जनवरी की शाम गांधीजी की हत्या के चलते वार्तालाप पूरा नहीं हो सका। लाइक अली और हैदराबाद प्रतिनिधिमण्डल तत्काल हैदराबाद लौट गया।

था। जैसाकि मुझे बताया गया कि निजाम के सलाहकारों ने उन्हें आश्वस्त किया कि यदि भारत आर्थिक प्रतिबंध थोपता है यह प्रभावी नहीं हो पाएंगे तथा आगामी कुछ महीनों तक हैदराबाद अपने पांवों पर खड़ा रह सकेगा, और इस अवधि में दुनियाभर में जनमत को अपने पक्ष में खड़ा किया जा सकेगा। भारत को काफी कमजोर और उस समय तथा कभी भी सैन्य कार्रवाई हेतु अक्षम ठहराया गया। सभी मुस्लिम देश हैदराबाद के साथ दोस्ताना थे और वे उसके विरुद्ध किसी सैन्य कार्रवाई को नहीं होने देंगे। हैदराबाद रेडियो तो इस घोषणा करने की हद तक चला गया कि यदि हैदराबाद के विरुद्ध युद्ध छेड़ा गया तो हजारों पाकिस्तानी भारत की ओर मार्च कर देंगे।

5 अप्रैल, 1948 को लाइक अली ने सत्रह पृष्ठों का टाइप किया हुआ एक बहुत लम्बा पत्र नेहरू को भेजा, जिसमें स्टैन्ड्स्टल एग्रीमेंट की शर्तो के उल्लंघन के आरोपों को नकारा और उल्टे भारत पर आरोप मढ़ दिए।

उसी दिन, निजाम ने लार्ड माऊंटबेटन को पत्र लिखकर कहा कि स्टेट मंत्रालय का पत्र 'दोस्ताना सम्बन्धों के खुले उल्लंघन के अल्टीमेटम के रूप में पूर्व भूमिका जैसा है।'

16 अप्रैल को लाइक अली की सरकार से बातचीत हुई जिसमें मैं भी उपस्थित था। सरदार ने कहा: आप भी जानते हो और मैं भी कि शक्ति किसके हाथों में है और हैदराबाद में वार्ताओं को अंतिम रूप से सिरे चढ़ाने का अधिकार किसके पास है। वह महाशय (कासिम रिजवी) जो हैदराबाद पर हावी हैं, ने अपना जवाब दे दिया है। उसने साफ तौर पर कहा कि यदि भारतीय रियासत हैदराबाद आती है तो उसे डेढ़ करोड़ हिन्दुओं की हड्डियों और राख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। यदि यह स्थिति है तो यह गंभीर रूप से निजाम और उनके खानदान के समूचे भविष्य को खोखला कर देगी। मैं आप से इसलिए साफ-साफ बोल रहा हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी गलत आशंका में रहें। हैदराबाद समस्या का भी उसी तरह से समाधान किया जाएगा जैसे अन्य राज्यों के सम्बन्ध में किया गया है। कोई अन्य संभावना नहीं है। हम एक ऐसी अलग-थलग जगह को बनाए रखने के पक्ष में सहमत नहीं हो सकते जो हमारे संघ जिसे हमने अपने खून और पसीने से बनाया है, को नष्ट करे। साथ ही साथ हम दोस्ताना सम्बन्ध और दोस्ताना समाधान चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं होगा कि हम कभी भी हैदराबाद की स्वतंत्रता पर राजी होंगे। यदि यह एक स्वतंत्र दर्जा बनाए रखने की जिद पर अड़े रहते हैं तो यह असफल रहेगा।''

निष्कर्ष रूप में सरदार ने लाइक अली से हैदराबाद वापस जाकर निजाम से सलाह कर एक अंतिम फैसला लेने को कहा ताकि 'पता चल सके कि हम दोनों कहां खड़े हैं।'

बातचीत के दौरान लाइक अली बेचैन दिख रहा था। मुझे ऐसा लगा कि सरदार ने जिस स्पष्टता से बात की उससे वह पूरी तरह से हक्का-बक्का रह गया।

हैदराबाद के सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की जाए के प्रश्न को लेकर भारत सरकार के सलाहकारों में सर्वसम्मति नहीं थी। जो वर्ग झुकने की नीति की वकालत कर रहा था उसके पास यह बहाना तैयार था कि इससे व्यापक स्तर पर साम्प्रदायिक अव्यवस्था फैलेगी जिससे हैदराबाद की तरफ से कोई कार्रवाई होगी। उनके आशंका थी कि हैदराबाद में हिन्दुओं को कत्ल कर दिया जाएगा और भारत में मुस्लिमों का कत्लेआम होगा। कुछ का कहना था इससे दक्षिण भारत में मुस्लिमों में विद्रोह होगा, विशेषकर मोपलाओं में। यह दिलचस्प सुझाव उन लोगों द्वारा दिया गया था जिन्होंने कभी एक मोपला को देखा तक नहीं था, उनकी मानसिकता के बारे में बहुत कम समझते थे और उस समय मालाबार की स्थिति के बारे में कुछ नहीं जानते थे। एक ऐसा और भय था कि यदि भारत ने हैदराबाद के विरूद्ध कोई कार्रवाई की तो पाकिस्तान हस्तक्षेप करेगा।

हैदराबाद के सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की जाए के प्रश्न को लेकर भारत सरकार के सलाहकारों में सर्वसम्मति नहीं थी। जो वर्ग झुकने की नीति की वकालत कर रहा था उसके पास यह बहाना तैयार था कि इससे व्यापक स्तर पर साम्प्रदायिक अव्यवस्था फैलेगी जिससे हैदराबाद की तरफ से कोई कार्रवाई होगी। उनके आशंका थी कि हैदराबाद में हिन्दुओं को कत्ल कर दिया जाएगा और भारत में मुस्लिमों का कत्लेआम होगा। कुछ का कहना था इससे दक्षिण भारत में मुस्लिमों में विद्रोह होगा, विशेषकर मोपलाओं में।

मेरा अपना मत था कि पाकिस्तान निश्चित रूप से हैदराबाद के मुद्दे पर भारत के साथ युद्ध का जोखिम मोल नहीं लेगा।

कुछ इस आशय का प्रचार भी चल रहा था कि हैदराबाद के विमान बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली जैसे शहरों पर बम बरसा सकते हैं। इस प्रचार से पड़ोसी राज्यों के लोगों में कुछ हद तक आशंकाएं घर कर गई थीं।

इस दौरान लाइक अली दवाब डाल रहा था कि हैदराबाद के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया जाए।

इसी बीच नई दिल्ली में अमेरिका चार्ज डी' अफेयर्स ने हमें बताया कि निजाम ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनसे मध्यस्थ बनने का अनुरोध किया है, जिसे ठुकरा दिया गया है।

रजाकरों ने मिशनरियों और ननों को भी नहीं बख्शा। स्टेट मिनिस्ट्री को सितम्बर की शुरूआत में शिकायतें मिलीं कि कुछ विदेशी मिशनरियों पर हमले किए गए हैं और रजाकरों ने कुछ ननों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है।

सेना का मानना था कि यह अभियान तीन सप्ताह से ज्यादा नहीं चलेगा। वास्तव में, सभी कुछ एक सप्ताह से कम समय में ही हो गया।

9 सितम्बर को, सभी पहलुओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करके और जब यह साफ हो गया कि भारत सरकार के पास कोई और विकल्प शेष नहीं बचा है तो हैदराबाद में सैनिक टुकड़ियां भेजने का निर्णय लिया गया ताकि राज्य में शांति और सद्भावना पुनर्स्थापित की जा सके तथा संलग्न भारतीय भू-भाग में सुरक्षा की भावना कायम हो सके। यह निर्णय दक्षिण कमाण्ड को सूचित कर दिया गया, जिसने आदेश दिया कि भारतीय फौजें 13 तारीख की तड़के सुबह हैदराबाद की तरफ कूच करेंगी।

भारतीय सेना का नेतृत्व मेजर-जनरल जे.एन. चौधरी कर रहे थे जोकि दक्षिण कमाण्ड के जनरल ऑफिस कमांडिंग-इन-चीफ लेटिनेंट जनरल महाराज श्री राजेन्द्रसिंह जी के निर्देश में काम कर रहे थे। सेना मुख्यालय द्वारा इस अभियान का नाम 'ऑपरेशन पोलो' रखा गया।

पहले और दूसरे दिन कुछ कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इसके पश्चात् प्रतिरोध कमजोर पड़ा और वास्तव में समाप्त हो गया। हमारी सेना को कुल मिलाकर बहुत कम हानि पहुंची लेकिन दूसरी ओर अव्यवस्थित अभियानों और अनुशासन की कमी, सशस्त्र सेना से असंबद्ध और रजाकरों को तुलनात्मक रूप से भारी क्षति उठानी पड़ी। मृतकों की संख्या 800 से कुछ ज्यादा थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस कार्रवाई में इतने अधिक लोग मारे गए, यद्यपि जब राज्य में रजाकरों द्वारा हिन्दुओं की हत्याओं, बलात्कारों और लूटमार के ताण्डव की तुलना की जाए तो यह संख्या ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।

17 सितम्बर की शाम को हैदराबाद की सेना ने हथियार डाल दिए। 18 को मेजर-जनरल चौधरी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने हैदराबाद शहर में प्रवेश किया। अभियान मुश्किल से 108 घंटे चला।

17 सितम्बर को लाइक अली और उनके मंत्रिमण्डल ने अपना इस्तीफा दे दिया। निजाम ने इसे के.एम. मुंशी को भेजा (जो पुलिस कार्रवाई शुरू होते ही नजरबंद कर दिए गए थे) और उन्हें सूचित किया कि उन्होंने अपनी सेना को समर्पण करने का आदेश दिया है, और वह एक नई सरकार का गठन करेंगे, कि भारतीय सेना सिकन्दराबाद, बोलारम जाने के लिए स्वतंत्र हैं तथा रजाकरों पर प्रतिबन्ध लगाया जाएगा। मुंशी ने यह जानकारी भारत सरकार को दी। मेजर-जनरल चौधरी ने 18 सितम्बर को मिलिट्री गवर्नर के रूप में दायित्व संभाला। लाइक अली मंत्रिमण्डल के सदस्यों के नजरबंद कर दिया गया। 19 सितम्बर को रिजवी गिरफ्तार कर लिया गया।

इस अभियान के दौरान समूचे भारत में कहीं भी कोई एक साम्प्रदायिक घटना नहीं घटी। हैदराबाद प्रकरण में सफलता से, तेजी से सभी ओर खुशी का माहौल था तथा देश के सभी भागों से इसके लिए भारत सरकार को मिल रहे बधाई संदेशों की बाढ़ सी आ गई थी।

17 सितम्बर को लाइक अली और उनके मंत्रिमण्डल ने अपना इस्तीफा दे दिया। निजाम ने इसे के.एम. मुंशी को भेजा (जो पुलिस कार्रवाई शुरू होते ही नजरबंद कर दिए गए थे) और उन्हें सूचित किया कि उन्होंने अपनी सेना को समर्पण करने का आदेश दिया है, और वह एक नई सरकार का गठन करेंगे, कि भारतीय सेना सिकन्दराबाद, बोलारम जाने के लिए स्वतंत्र हैं तथा रजाकरों पर प्रतिबन्ध लगाया जाएगा। मुंशी ने यह जानकारी भारत सरकार को दी। मेजर-जनरल चौधरी ने 18 सितम्बर को मिलिट्री गवर्नर के रूप में दायित्व संभाला।

टेलपीस (पश्च्यलेख)

अपने एक पूर्ववर्ती ब्लॉग में मैंने 1947 के एक आईएएस अधिकारी एम. के.के. नायर की पुस्तक "विद नो इल फीलिंग टू एनी बॉडी" के आधार पर मैंने पॉयनियर में प्रकाशित एक रिपोर्ट उद्धृत की थी जिसमें कहा गया था कि सरदार पटेल केबिनेट की एक बैठक से बहिर्गमन कर गए थे क्योंकि प्रधानमंत्री की कुछ टिप्पणियों से वह आहत हुए। पुस्तक यह भी कहती है कि नेहरू, पटेल की पुलिस कार्रवाई के बजाय संयुक्त राष्ट्र संघ का रास्ता अपनाने के पक्ष में थे। ■

सीबीआई कामकाज में जीओएम की सिफारिशें मात्र-एक छल

अरुण जेटली

कोल-ब्लॉक आबंटन घोटाले के मामले में यूपीए सरकार के कानून मंत्री तथा पीएमओ के विधि अधिकारी एवं अन्य अधिकारी सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट को सिखाने-पढ़ाने के प्रयास में लगभग रंगे हाथों पकड़े गए थे। सरकार और सीबीआई ने इस विषय में जो कुछ भी किया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी प्रगट की। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है जिसमें वह उन कदमों का विस्तृत विवरण दे जिससे सरकार ऐसी स्थिति से मुक्त हो सके। इस घुटने-टेक सरकार ने एक मंत्री समूह का गठन कर उससे सीबीआई के कामकाज के तौर-तरीकों और सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल किए जाने वाले हलफनामें के प्रस्तावित प्रारूप पर समुचित सिफारिशें देने को कहा गया है। अब मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि केबिनेट ने इस मंत्र समूह की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इन सिफारिशों में एजेंसी को अधिक वित्तीय शक्तियां, सरकारी अधिकारियों की जांच पर एक समयबद्ध स्वीकृति का प्रावधान, एक कालेजियम द्वारा निदेशक की नियुक्ति और सेवानिवृत्त जजों के पैनल के गठन की बात कही गई है जो इस जांच पर निगरानी रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बाहर की तरफ से किसी प्रकार प्रभाव न डाला जा सके।

सरकार ने ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश की है जैसे कि मंत्री समूह के सिफारिशों के आधार पर कोई नया निर्णय लेने के लिए कोई बड़ा भारी कारनामा कर दिखाया है। केबिनेट की बैठक में लिया गया निर्णय सीबीआई को राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त नहीं करता है।

हमारी राय है कि सीबीआई के राजनैतिक हस्तक्षेप के भारी दुरूपयोग के कारण इसकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। अतः, इस कलंक को धोना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार आवश्यक है कि सीबीआई को ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों में भारत सरकार के कार्मिक विभाग से लोकपाल को स्थानांतरित किया जाए।

सीबीआई के कामकाज पर संसद के दोनों सदनों में बहस हुई थी और यह लोकपाल सम्बन्धी कानून के मसौदे पर सार्वजनिक बहस का विषय बना रहा है। कानून बनाने का आवश्यक प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि सीबीआई स्वतंत्र होकर काम करे और कैसे इसे राजनैतिक हस्तक्षेप से बचाया जा सके। लोकसभा में बिल पारित हुआ परन्तु बहुमत से राज्यसभा ने कुछेक अर्थपूर्ण संशोधनों पर जोर दिया जिसके कारण सरकार ने सदन के स्थगित करा डाला। राज्य सभा की प्रवर समिति का गठन किया गया जिससे एक समुचित समय में लोगों के सुझाव मांगे थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम तीन लोगों ने, जिसमें श्री राजीव प्रताप रूड़ी, श्री भूपेन्द्र यादव तथा मैं शामिल थे, सीबीआई के कामकाज पर निम्नलिखित सुझाव दिए थे:

''उपर्युक्त कथन के आधार पर हमारी राय है कि सीबीआई के राजनैतिक हस्तक्षेप के भारी दुरूपयोग के कारण इसकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। अतः, इस कलंक को धोना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार आवश्यक है कि सीबीआई को ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों में भारत सरकार के कार्मिक विभाग से लोकपाल को स्थानांतरित किया जाए। वैकल्पिक रूप से, सीबीआई की स्वतंत्रता बरकरार रखने तथा राजनैतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए हमने अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित सुझाव देते हैं:-

- सीबीआई के दो विंग होंगे। सीबीआई निदेशक पूरे संगठन के अध्यक्ष होंगे। उनके अधीन अलग अभियोजन निदेशालय को कार्य करना चाहिए।
- सीबीआई इन्वेस्टिंग विंग और अभियोजना विंग को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए।
- सीबीआई निदेशक और अभियोजन निदेशक की नियुक्ति एक कोलेजियम करे जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और लोकपाल का अध्यक्ष शामिल रहेंगे।
- सीबीआई निदेशक तथा अभियोजन

निदेशक का एक निश्चित कार्यकाल हो।

- सीबीआई निदेशक और अभियोजन निदेशक दोनों को ही सेवानिवृत्ति के बाद सरकार में पुन: नियुक्ति करने पर विचार नहीं किया जा सकेगा।
- लोकपाल को भेजे गए मामलों के बारे में सीबीआई के अधीक्षण और निर्देशन की शक्तियां लोकपाल के पास ही रहेंगी।
- यदि किसी भी कारणवश किसी मामले के जांचकर्ता अधिकारी का तबादला किया जाता है तो उसके लिए लोकपाल की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।
- सीबीआई की तरफ से कोर्ट में पेश होने वाले और परामर्श देने वाले एडवोकेटों के पैनल को सरकार से स्वतंत्र करना होगा। उनकी नियुक्ति लोकपाल की पूर्व स्वीकृति से अभियोजन निदेशक कर सकेगा।''

उपर्युक्त सुझावों में से प्रवर समिति ने एक को छोड़कर शेष सभी सुझावों को मान लिया और जिसे नहीं माना गया, उसका सम्बन्ध सरकार में सेवानिवृत्ति के बाद सीबीआई निदेशक और अभियोजन निदेशक को पुन: नियुक्ति किए जाने से है। उक्त सिफारिशों को 31.1.2013 को केबिनेट के सामने रखा गया और कुछेक मामूली संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। क्योंकि यह समिति सदन ने गठित की थी, इसलिए प्रवर समिति की सिफारिशें संसद की सम्पत्ति हैं। सरकार और कोई भी सदस्य इसमें संशोधन करने का प्रस्ताव कर सकता है। अत:, जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सीबीआई को राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्ति के लिए उपायों को उल्लेख करने के बारे में आदेश पारित किया तो सरकार को संसदीय प्रवर समिति के सर्वसम्मत सिफारिशों को रखना चाहिए था जिस पर यूपीए संसद सदस्यों की सहमति थी तथा उस पर भाजपा के उस अतिरिक्त नोट को भी रखना चाहिए था जिसमें सीबीआई के कामकाज पर निष्पक्ष कार्य सुनिश्चित करने का उद्देश्य निहित था। इस पूरे पैकेज में ऐसी व्यवस्था थी जिससे स्वतंत्र प्रक्रिया द्वारा निदेशक की नियुक्ति होना, अभियोजन निदेशक को अलग रखना था ताकि स्वतंत्र आधार पर कामकाज हो सके, न कि विधि मंत्रालय का डेपुटेशन पर कोई अधिकारी आकर काम करने लगे। इसमें इन उच्च पदों पर एक निश्चित काल की नियुक्ति का प्रावधान भी था, ऐसा करने से सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों का पक्षपात करने से भी बचा जा सकता था क्योंकि एक निश्चित काल का कार्यकाल होने के साथ ही साथ इसमें सरकार में पुन: नियुक्ति पर भी विचार नहीं किया जा सकता था। सीबीआई की अधीक्षण और निर्देशन की शक्तियां लोकपाल के पास निहित रहनी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ही अपीलीय अथारिटी रहनी थी। संवेदनशील मामलों के जांचकर्ता अधिकारियों को लोकपाल की अनुमति के बिना तबादला नहीं किया जा सकता था। सीबीआई की तरफ से पेश होने और परामर्श देने वाले एडवोकेटों का पैनल सरकारी वकीलों से स्वतंत्र रहना था क्योंकि सरकारी एडवोकेटों और कानूनी अधिकारियों की नियुक्ति में पर्याप्त राजनीतिकरण हुआ करता है। यह प्रवर समिति की सिफारिश थी। 31 जनवरी 2013 को केबिनेट ने इसकी स्वीकृति दी थी। अत:, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा तो यह एक ऐसा वर्तमान निर्णय था जिसे मात्र सुप्रीम कोर्ट के सामने रख देना चाहिए था। मंत्री समूह की सिफारिशें तथा केबिनेट की स्वीकृति में उपुर्यक्त सुझावों की अनदेखी की गई है और सीबीआई को सेवानिवृत्त जजों के प्रति जवाबदेह बना दिया गया है। इन सेवानिवृत्त जजों का चयन कौन करेगा जिनके प्रति सीबीआई जवाबदेह होगी? सेवानिवृत्त जजों की भरमार है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो न्यायिक मूल्यों से बंधे होते हैं। फिर भी,ऐसे बहुत से लोग हैं जो निरंतर सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी की तलाश में रहते हैं।

सेवानिवृत्त जज एक प्रकार से गैर-जवाबदेही वाले इंस्टीट्यूशन होते हैं बहुत से सेवानिवृत्त जजों के सामने रिटायरमेंट के बाद नौकरी पर रखना लगभग वैधानिक अधिकार बनता जा रहा है। मैंने यह बात बार-बार कही है कि यदि देश की स्वतंत्र न्यायपालिका को मजबूत करना है तो हमें सेवानिवृत्ति के बाद रिटायर्ड जजों की नियुक्ति कि इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना आवश्यक है। अभी हाल में ही एक रिटायर्ड जज को श्रीमती सुषमा स्वराज और मेरी अपनी सहमति न होने पर भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बना दिया गया। जज के रूप में उन्होंने जिस प्रकार की भूमिका निभाई थी, उसे देखते हुए सेवानिवृत्ति के बाद उनकी नियुक्ति न्यायसंगत नहीं थी।

सेवानिवृत्त जज एक प्रकार से गैर-जवाबदेही वाले इंस्टीट्यूशन होते हैं बहुत से सेवानिवृत्त जजों के सामने रिटायरमेंट के बाद नौकरी पर रखना लगभग वैधानिक अधिकार बनता जा रहा है। मैंने यह बात बार-बार कही है कि यदि देश की स्वतंत्र न्यायपालिका को मजबूत करना है तो हमें सेवानिवृत्ति के बाद रिटायर्ड जजों की नियुक्ति कि इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना

....शेष पृष्ठ 24 पर

डॉ. मुकर्जी ने काश्मीर का भारत के साथ विलय के लिए किया बलिदान

हमारे संवाददाता द्वारा

स्वतंत्र भारत में पहला बलिदान करने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी को भाव-भीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई, उन्होंने 60 वर्ष पूर्व जम्मू-काश्मीर को भारत संघ के साथ सम्पूर्ण विलय करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी और वे चाहते थे कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों द्वारा भारत को स्वतंत्र करने के बाद जिस तरह से शेष सभी राज्यों ने

स्वतंत्र भारत के साथ विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, उसी तरह जम्मू कश्मीर का भी भारत संघ के साथ विलय हो। नई दिल्ली में 25 जून 2013 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी रिसर्च फाउण्डेशन और डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास ने संयुक्त रूप से 'भारत की राष्ट्रीय पहचान और सुरक्षा को खतरा' विषय पर चर्चा कर राष्ट्रीय एकता और विकास का आह्वान किया। इस बैठक की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध भाजपा नेता और पूर्व विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह ने की। पूर्व जम्मू-कश्मीर तथा असम के राज्यपाल ले. जन. (सेवानिवृत्त) एस. के. सिन्हा, पीवीएसएम माननीय अतिथि रहे और पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो निदेशक श्री अजीत डोवाल, के सी विशेष अतिथि थे। भाजपा महासचिव (संगठन) श्री रामलाल ने भी अपनी पैनी टिप्पणियों से दर्शकों को प्रोत्साहित कर प्रेरणा दी।

अपने सम्बोधन में श्री अजीत डोवाल ने कहा कि भारत वह वटवृक्ष है जिसके आस-पास अनेकों छोटे-छोटे पौधों से उभरने से इसकी तस्वीर खराब करके रख दी है। इन छोटे-मोटे पौधों के उगने से इस महावृक्ष की महान संस्कृति, इतिहास, एकता और अखण्डता अवरूद्ध होती है।

जनरल सिन्हा ने अवैध अप्रवासियों की अनवरूद्ध बाढ़ से पैदा होने वाली भारत की राष्ट्रीय पहचान और सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा की, जिसके कारण पूर्वोत्तर राज्यों की जनसांख्यिकीय बुरी तरह से प्रभावित हुई है।

श्री रामलाल ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर ने हमारे प्रधानमंत्रियों में से एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। श्री रामलाल ने प्रश्न करते हुए पूछा कि ये कितना प्राचीन है? भारत का 5000 से अधिक वर्षों का पुराना इतिहास और संस्कृति है। परन्तु कुछ विभाजनकारी तत्व ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुगलों और अंग्रेजों के आक्रमण से भारत के इतिहास का आरम्भ होता है। यही वे लोग हैं जो वर्तमान पीढ़ी को भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को अपने गौरवान्वित तथा समृद्ध विगत से अलग कर रहे हैं, जबकि यही देश के राष्ट्रवाद और इसकी विशिष्ट पहचान की नींव है। उन्होंने श्रोताओं से अपील की कि वे देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की रक्षा में अपना सब कुछ झोंक दें क्योंकि यह जाति, क्षेत्र और धर्म के संकीर्ण दायरे से कहीं बड़ा उच्च स्थान रखती है।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री जसवंत सिंह ने कहा कि भारत ने अपना स्वतंत्रता संघर्ष 'वन्दे मातरम्' और 'जयहिंद' के नारे से किया था। स्वतंत्रता के बाद, 'जय हिन्द' को राष्ट्रीय सलामी का प्रतीक बनाया गया। परन्तु उन्होंने पूछा कि आज वह 'हिन्द' कहां है जिसकी 'जय' की प्रार्थना हम प्रतिदिन करते हैं। भारत का वह संविधान जो प्रमुख रूप से ब्रिटिश रचित गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट 1935 पर आधारित है, ''हिन्द'' पर एकदम खामोश है।

फाउण्डेशन के कोषाध्यक्ष श्री श्याम जाजू ने विशिष्ट जनों को सम्बोधित करते हुए श्री मुकर्जी के योगदान का विस्तृत उल्लेख किया।

कार्यक्रम का संचालन मुकर्जी फाउण्डेशन के सचिव श्री अरूण सिंह ने किया। बैठक में उपस्थित विशिष्ट जनों में मुकर्जी स्मृति न्यास के श्री एम. वेंकैया नायडु, अध्यक्ष, डॉ. नन्द किशोर गर्ग, सचिव और श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कोषाध्यक्ष तथा पूर्व सीएजी श्री टी.एन चतुर्वेदी शामिल थे। ■

कांग्रेस की राजनीति में राष्ट्रधर्म के लिए जगह नहीं : मीनाक्षी लेखी

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता व जानी-मानी अधिवक्ता श्रीमती मीनाक्षी लेखी का कहना है कि पार्टी तो प्रतिदिन संप्रग शासन में हो रहे घोटालों को प्रकाश में ला रही है। लेकिन मीडिया उसे ठीक से प्रस्तुत नहीं कर रहा, इसलिए हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि पार्टी की बात जनता तक कैसे पहुंचे? हमें अपने प्रचार-तंत्र को और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही संगठन को सशक्त करने के लिए बड़े पैमाने पर सदस्यता की मुहिम चलाने की जरूरत है। ऑनलाइन सदस्यता के माध्यम से भी लोगों को जोड़ सकते है। सांप्रदायिकता के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश भर में हुए दंगों का इतिहास बताता है कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी है। श्रीमती लेखी ने कहा कि राष्ट्रवाद भाजपा की विचारधारा है और हमने अटलजी के नेतृत्व वाली राजग सरकार और गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अनेक भाजपा शासित राज्यों में सुशासन के नए मानदंड स्थापित किए हैं।

गत 24 जून 2013 को 'कमल संदेश' कार्यालय संगोष्ठी कक्ष में आयोजित सामूहिक चर्चा में श्रीमती लेखी ने संपादकीय मंडल के साथ कई समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर भाजपा साहित्य एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री अम्बाचरण वशिष्ठ भी उपस्थित थे। प्रस्तुत है प्रमुख अंश:-

शिवशक्ति बक्सी : राजनीतिक दलों में युवाओं की भागीदारी को आप कैसे देखती हैं? एक शब्द है टैलेंट हंटिंग। कॉरपोरेट सेक्टर हो या सोशल सेक्टर। ये चाहे तो आवेदन दें और हजारों लोग इनके पास आएं, लेकिन ये जाते हैं कैम्पसेज में, इनका एचआर डिपार्टमेंट हरेक कैम्पस में जाता है और प्रतिभाओं को खोजकर लाता है। पार्टी में भी टैलेंट हंटिंग का कोई न कोई मैकेनिज्म ढूढ़ना चाहिए। वास्तविक युवा नेतृत्व और महिला नेतृत्व को कैसे उभारा जाय?

मीनाक्षी लेखी (मी. ले.) : जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, यह एक 'क्लोज्ड सिस्टम' है, यहां युवाओं के लिए कोई जगह नहीं है। भाजपा एक लोकतांत्रिक दल है जहां युवाओं के लिए अपार अवसर हैं। भारतीय जनता पार्टी में युवा और महिला नेतृत्व को उभारने के लिए प्रयास होते रहते हैं। पार्टी के दो सशक्त मोर्चे हैं- युवा मोर्चा और महिला मोर्चा। दोनों मोर्चे अनेक विषयों पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसके साथ ही युवाओं और महिलाओं को पार्टी से जोड़ने पर बल दिया जाता है। मैं मानती हूं कि बड़े पैमाने पर सदस्यता मुहिम चलाने की आवश्यकता है और इसमें ऑनलाइन सदस्यता से काफी तेजी आ सकती है।

अम्बा चरण वशिष्ठ : राजग में पहले दो दर्जन दल थे। हाल ही में जद(यू) भी इससे अलग हो गया। अब इसके साथ चार-पांच दल रह गए हैं। ऐसे में राजग का विस्तार कैसे होगा?

मी. ले. : जिस तरीके की राजनीति जद(यू) भाजपा के साथ कर रहा था, चाहे वो श्री नरेंद्र मोदी को लेकर हो, चाहे भाजपा के बारे में अनाश-शनाप बोलने को लेकर हो, चाहे आर.एस.एस. के विषय में कहने की हो, वो बहुत घटिया राजनीति कर रहा था, हम उसके साथ खड़े हो ही नहीं सकते थे। लेकिन हम पहल नहीं करना चाहते थे, हमारा विषय बहुत स्पष्ट था कि हमें जो जनादेश है वो जदयू-भाजपा को इकट्ठा लोगों ने दिया है सरकार चलाने के लिए, उस जनादेश के विरोध में हम खड़े होना नहीं दिखना चाहते, लेकिन जद(यू) ने सरकार बनाने के लिए जिनके विरोध में चुनाव लड़ा, यानी कांग्रेस के खिलाफ लड़ा, अब विडंबना देखिए, कांग्रेस की मदद से वो सरकार चल रही है। मैं कहती हूं वो भ्रष्टाचार की गोंद में चिपक गए हैं। अब सपा, बसपा, जद(यू) एक ही कैटेगरी के दल हो गए, तो जाहिर सी बात है

कि हम इनके साथ खड़े नहीं हो सकते। अगर अपने नेतृत्व पर विश्वास था जद(यू) को, तो इन्हें दुबारा से चुनाव में जाना चाहिए था। लोगों का मत लेकर दुबारा सरकार बनाते, वो तो किया नहीं, वो तो भाजपा के वोटर के साथ सरकार बनी, तो उसको इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस की मदद से सरकार चला रहे हैं, इसलिए यह अवसरवादी राजनीति है। इसका हमें कोई नुकसान नहीं है। आप देखिए, क्या भाजपा कांग्रेस की मदद से सरकार चला सकती है? आप विपक्षी दल हो, सरकार की नीतियों के खिलाफ हो। उनकी नीतियों के खिलाफ होकर उनकी सहायता से सरकार चलाया। जिस असली कारण से यह गठबंधन टूटा, वो सामने आ गया। असली गठबंधन टूटा क्योंकि वो कांग्रेस के साथ चल रहे थे, वो लोगों को दिखाई दे गया, हम तो इनके साथ हो ही नहीं सकते थे।

अम्बा चरण वशिष्ठ : जद(यू) भाजपा के बल पर बढ़ा। अन्यथा वह दूसरे राज्यों में क्यों नहीं पनप सका? गुजरात में अकेले लड़ा, 1 सीट नहीं आई। उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ा तो कुछ नहीं हुआ। तो यह तो भाजपा के समर्थन से ही आगे आ सका।

मी. ले. : देखिए, जो बिहार का हमारा वोटर है। वो हमसे परेशान था। जब मेरी पहली प्रेस-कांफ्रेंस थी तो मैंने कहा था कि जद(यू) के प्रमाणपत्र की हमें जरूरत नहीं है। उनको असांप्रदायिकता का प्रमाण-पत्र कांग्रेस ने दिया, प्रधानमंत्री ने दिया। दुनिया जानती है कि हम कौन हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं। जो संप्रदाय को लेकर वोट-बैंक की राजनीति करते हैं, उनको लोग देख रहे हैं। जिस तरह से वे बोल रहे थे, जिस तरह से वो हमारे साथ व्यवहार कर रहे थे, हमारे लोग हमसे खफा थे कि हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? यह तो वही हुआ, जिस थाली में खाना, उस थाली में छेद करना।

राम प्रसाद त्रिपाठी : भाजपा पर कांग्रेस सहित अनेक दल सांप्रदायिक होने का आरोप लगाते हैं। क्या कहेंगी आप?

मी. ले. : देश में जितने दंगे हुए कांग्रेस पार्टी ने करवाए। यहां तक कि गुजरात में 2002 के दंगे में इनकी पार्टी के नेता शामिल थे गुलबर्ग सोसाइटी-जहां एहसान जाफरी का कांड हुआ था, इसे मेर सिंह चौधरी ने अंजाम दिया था, जो कांग्रेस का पार्षद था। बड़ौदा का कांग्रेसी महापौर शामिल था दंगों में। गोधरा में जो ट्रेन जली, उसको जो जलानेवाले थे, उनमें कांग्रेस के नेता शामिल थे। उनके घरों से कैरोसिन, पेट्रोल वगैरह निकला, तो हर दंगे में तो ये शामिल हैं। 1986 में मुरादाबाद के दंगे हुए। मलियाना के दंगों का क्या इतिहास है। मेरठ के दंगों का क्या इतिहास है। हाल ही में राजस्थान में भी इनके शासन में दंगे हुए, तो राजनीति के लिए ना इनकी सिद्धांतों पर आस्था है, ना ये राष्ट्रहित देखते हैं। ये समझौता एक्सप्रेस मामलों में आतंकवाद को लेकर राजनीति खेल सकते हैं। सीआईए की रिपोर्ट है कि ये आतंकी गतिविधियां आई.एस.आई. के द्वारा करवाई गई, इन्होंने किन लोगों को पकड़ा? 26/11 में आई.एस.आई. का हाथ था, इसको इन लोगों ने क्या रंग देने की कोशिश की? बाटला हाऊस में एनकाऊंटर हुआ तो उसमें आतंकवादी शामिल थे, इन्होंने इसको क्या राजनीति देने की कोशिश की, तो ये लोग क्या शिक्षा दे रहे हैं सांप्रदायिकता पर!

सत्यपाल : दिक्कत यही है कि विकास मुद्दा होना चाहिए लेकिन बेवजह सेक्युलरिज्म की रट लगाई जाती है। मतलब सिर्फ इतना है कि हिंदू और मुसलमान के बीच विभाजन करना।

मी. ले. : सही कह रहे हैं आप।

संजीव कुमार सिन्हा : लोग भाजपा के साथ क्यों जुड़ें? भाजपा ने ऐसा क्या किया है कि लोग कांग्रेस के साथ ना जुड़कर भाजपा के साथ जुड़ें?

मी. ले. : देखिए, भाजपा को जहां-जहां मौका मिला, तो हमने सुशासन दिया। चाहे वो एनडीए का समय था, चाहे वो उसके बाद के राज्यों में जहां-जहां भाजपा की सरकारें रहीं। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं गोवा सब जगह हमने सुशासन दिया और लोगों तक शासन की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, वो बताई। तो एक ऐसे मापदंड तय किए सुशासन के, कि सरकारें कैसी चलनी चाहिए, वो सबसे बड़ी उपलब्धि रही। दूसरा, जहां तक किसी भी राष्ट्र को राष्ट्र रहने के लिए एक कोई कोर विषय की आवश्यकता होती है, उसमें जो मुख्य विषय है वह है राष्ट्रवाद की विचारधारा, चाहें वो देश की सीमाएं को लेकर हों, चाहे वो शासन को लेकर हो, चाहे वो आम नागरिक के जीवन में सब सुख-सुविधा पहुंचाने को लेकर हो, चाहे वो सड़कें निर्मित करने को लेकर हों, चाहे वो हमारी जो आर्थिक समस्याएं हैं, उनसे जूझने को लेकर हों, उस सब में भाजपा ने एक उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

आज के जो मुख्य मुद्दे हैं, वे दो हैं- भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन का। जिस तरीके से सरकार की साख लगातार गिर रही है, उसी तरह से रुपए का अवमूल्यन

हो रहा है। नरेन्द्र मोदीजी ने ठीक कहा कि उन दोनों में प्रतिस्पर्धा है कि कौन पहले गिरेगा, तो उसको रोकने के लिए आपको भाजपा की तरफ देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, आर्थिक व्यवस्था को लेकर जिस तरीके की समस्या आज के युवा में है, जिस तरीके की बेचैनी है, दो हाथों को काम चाहिए, पेट को अनाज चाहिए, मस्तिष्क को जागरूक रहने के लिए कुछ विचार चाहिए, वो जो कमी है, उसको केवल और केवल भाजपा ने राजग के समय में की और आर्थिक व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया। और जब भी ये विषय उठाते हैं कि वैश्विक मंदी है तो हमारा जो समय था, उस समय हमने परमाणु विस्फोट किया था, आर्थिक मंदी तब भी थी, हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध थे, इन सब समस्याओं के रहते हुए भी हमने देश में विकास किया। हमने करोड़ों नौकरियां उपलब्ध कराई। आज अनेक मुद्दे जो जनता के सामने हैं, इन सब पर काम यदि करने हैं तो आपको भाजपा की तरफ ही देखना पड़ेगा। क्योंकि इनको आप साठ साल से मौका दे रहे हैं, तबाही मचाई हुई है, जिनको पांच-छह साल का मौका दिया उन्होंने काम करके दिखाया तो क्यों नहीं उनको दुबारा मौका मिले ताकि देश देश रह सके।

विकाश आनंद : अभी उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा आई हुई है, वहां के मुख्यमंत्री का कल वक्तव्य आया कि अभी 15 दिन और लग जाएंगे। हमने गुजरात में भुज का भूकम्प भी देखा है, इतना जल्दी सब इंतजाम हो गया।

मी. ले. : हमने उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा से हुई तबाही को 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित करने की मांग की है। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। यह कुशासन का परिणाम है।

राम प्रसाद त्रिपाठी : संप्रग सरकार में जितनी महंगाई, भ्रष्टाचार और कुशासन हुआ है क्या उसको भाजपा 2014 के आमसभा चुनाव से पहले लोगों तक पहुंचा पाएगी?

मी. ले. : देखिए, भाजपा तो पहुंचा रही है। और उसमें जाहिर सी बात है कि हमें सक्रिय रूप से मीडिया की आवश्यकता है। अगर आपने प्रश्नचिन्ह लगाना होगा उसके बाद भी, तो मीडिया पर जाएगा, हम पर नहीं जाएगा, हम तो रोज कोयला घोटाला की बात करते हैं, वो नहीं छाप रहे तो प्रश्न उनसे करना है कि कोई क्यों नहीं छाप रहा। या कोई उस बाइट को नहीं चला रहा तो टीवी वालों से प्रश्न करना है कि आप क्यों नहीं चला रहे। हम तो रोज कह ही रहे हैं। चाहे वो आइपीएल का मामला था, चाहे वो जिया खान के आत्महत्या का मामला था, ये सब चीजें यही दिखाती हैं कि लगातार ऐसी ही चीजों पर काम हो रहा है जो सीधे कांग्रेस पर प्रहार नहीं करती, इन दो मामलों का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं कि कोयला घोटाला दबा दिया गया, और साथ ही दबा दिया गया अगस्टावेस्टलैंड घोटाला को। आज लोग भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। ■

(प्रस्तुति : संजीव कुमार सिन्हा)

गुजरात में जिला पंचायतों और ताल्लुका पंचायत चुनाव में उल्लेखनीय विजय

गुजरात ने एक बार फिर कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को नकारा

2 जुलाई 2013 को जिला पंचायतों और ताल्लुका पंचायत चुनावों के परिणाम प्राप्त हुए। तीन जिला पंचायतों के चुनाव हुए, उन सभी तीन पंचायतों में भाजपा ने गौरवपूर्ण सफलता हासिल की तथा 19 ताल्लुका पंचायतों में से 12 पंचायतों में उसकी विजय हुई। कांग्रेस ने किसी जिला पंचायत में विजय प्राप्त नहीं की, और केवल 7 ताल्लुका पंचायतों में सफलता पाई। ये चुनाव गुजरात के सभी भागों में हुए, चाहे वह उत्तर गुजरात हो या मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात हो या फिर सौराष्ट्र। इन चुनावों से पूर्व, जिन तीन जिला पंचायतों में मतदान हुआ, उनमें से कांग्रेस ने 2 पंचायतों पर कब्जा जमा रखा था, और जिन 19 ताल्लुका पंचायतों में चुनाव हुआ था, उनमें से कांग्रेस का कब्जा 15 ताल्लुका पंचायतों पर था।

जिला पंचायत (मतदान सौराष्ट्र, मेहसाना और पोरबंदर जिलों में हुआ)

पंचायतों की संख्या	भाजपा	कांग्रेस	भाजपा (पूर्व संख्या)	कांग्रेस (पूर्व संख्या)
3	3	0	1	2

ताल्लुका पंचायत (मतदान- वलसाड़, सूरत, तापी, भरूच, वडोदरा, पंचमहला, दाहोद, आणंद, गांधीनगर, साबरकंठा, राजकोट, जूनागढ़ जिले)

पंचायतों की संख्या	भाजपा	कांग्रेस	भाजपा (पूर्व संख्या)	कांग्रेस (पूर्व संख्या)
19	12	7	4	15

पंथनिरपेक्षता के नाम पर भेदभाव

बलबीर पुंज

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हृदय से धन्यवाद दिया, क्योंकि जैसा कि वो कहते हैं, प्रधानमंत्री ने जदयू नेता की पंथनिरपेक्षता का समर्थन करते हुए उसको प्रमाणीकृत करने वाला बयान दिया। दिखने में लगता है, इस बहस में कि कौन कांग्रेस के लिए पंथनिरपेक्ष और कौन साम्प्रदायिक है, श्री नीतीश कुमार ने उस प्रमाणीकरण कार्य को आउटसोर्स कर दिया है। फिर भी, इनमें से कोई भी नेता, जो कांग्रेस द्वारा प्रमाणित पंथनिरपेक्ष/साम्प्रदायिक के तमगे को कृतज्ञतापूर्वक दर्शाते हैं, ऐसी पथभ्रष्ट किस्म की कवायद के परिणामों के बारे में नहीं सोचता। प्रधानमंत्री द्वारा नीतीश कुमार के पंथनिरपेक्ष होने के प्रमाणीकरण में यह आरोप निहित है कि बिहार के मुख्यमंत्री अब तक साम्प्रदायिक रहे हैं। नीतीश कुमार जैसे लोग पंथनिरपेक्ष व साम्प्रदायिक के बीच विभेद के लिए प्रमाणपत्र एक ऐसी पार्टी से लिए जाने के परिणामों की अनदेखी क्यों करते हैं जो स्वयं संदेह के घेरे में है?

बहस जब पंथनिरपेक्ष बनाम साम्प्रदायिक को लेकर होती है, तो इस मामले में कांग्रेस का रिकार्ड सर्वाधिक संदिग्ध रहा है। विकासीय परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले वित्तपोषण में प्राथमिकता किसे दी जानी चाहिए? स्वाभाविक रूप से निर्धनतम में निर्धन को। लेकिन श्री सिंह ने कुछ समय पूर्व जो जवाब दिया था वह सबसे ज्यादा साम्प्रदायिक जवाब था। उन्होंने कहा, अल्पसंख्यकों (अर्थात् मुसलमानों) को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यदि कांग्रेसनीत संप्रग सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए घोषित 15 सूत्रीय कार्यक्रमों पर दृष्टि डाली जाए तो क्या इस सरकार की साम्प्रदायिक प्रकृति के बारे में कोई संदेह बाकी रह जाता है। अन्य प्रमाणकृत पंथनिरपेक्षतावादियों में से एक हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी, जिनकी सरकार अब मुसलमान धर्मगुरुओं को वेतन सुविधा प्रदान कर रही है। ऐसे स्वयंभू पंथनिरपेक्षतावादी न केवल धर्मगुरुओं, नेताओं व अल्पसंख्यक समुदाय के बुद्धिजीवियों के एक तबके द्वारा किए जाने वाले धार्मिक अतिवाद और राजनीतिक नृजातिवाद को सहन करते हैं बल्कि उनको खुश करने व उनके समक्ष नतमस्तक होने पर उतारू रहते हैं। सोचिए किस तरह पश्चिम बंगाल सरकार ने विख्यात लेखक सलमान रश्दी को कोलकाता में कदम रखने या तस्लीमा नसरीन को पश्चिम बंगाल में रहने की अनुमति नहीं दी।

केन्द्र की ओर वापस लौटते हैं, जहां संप्रग सरकार अब मदरसों द्वारा जारी किए जाने वाले मैट्रिक पास होने के प्रमाणपत्रों मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्डो द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्रों के समकक्ष दर्जा दे रही है। यह इस तथ्य के बावजूद कि अधिकतर मदरसे अत्यधिक साम्प्रदायिक किस्म की शिक्षा देते हैं। असलियत में, मदरसे सामान्यत: भारतीय इतिहास के बारे में पेचीदा किस्म के दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षा देते हैं जिसके अंतर्गत मुस्लिम शासकों के आक्रमण के पूर्व की भारतीय सभ्यता को नीची दृष्टि से देखा जाता है। खलीफा की संस्था, जिसे तुर्कों ने स्वयं उखाड़ फेंका था, उसकी प्रशंसा की जाती है। युवा मुसलमान मध्यकालीन दौर से बंधे रहते हैं यद्यपि वे तेजी से आधुनिकीकृत होते जगत में रह रहे हैं।

प्रधानमंत्री द्वारा नीतीश कुमार के पंथनिरपेक्ष होने के प्रमाणीकरण में यह आरोप निहित है कि बिहार के मुख्यमंत्री अब तक साम्प्रदायिक रहे हैं। नीतीश कुमार जैसे लोग पंथनिरपेक्ष व साम्प्रदायिक के बीच विभेद के लिए प्रमाणपत्र एक ऐसी पार्टी से लिए जाने के परिणामों की अनदेखी क्यों करते हैं जो स्वयं संदेह के घेरे में है?

शिक्षा के प्रति अधिकतर मदरसों का दृष्टिकोण सऊदी अरब केंद्रित है। प्रतिष्ठित अमेरिकी विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे पश्चिम एशिया के कुछ विद्वानों ने ऐसी मानसिकता धारण की है जो ऐसी शिक्षा के माध्यम से उग्रपंथी इस्लामवाद को जन्म देती है। इस बीच, भारत में अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकतर बच्चे समावेशी एवं पंथनिरपेक्ष शिक्षा ग्रहण करते हैं।

भारत सरकार से अपेक्षा की जाती है किवह आतंकवाद से संघर्ष करेगी। लेकिन वह कैसे संकीर्ण मानसिकता वाली, धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देती है और उसे पंथनिरपेक्ष, वैज्ञानिक एवं तर्कसंगतता आधारित शिक्षा के समकक्ष

मानती है? परिणामस्वरूप, एक देश में अब दो शिक्षा प्रणालियां हैं प्रकारांतर से जिसका अर्थ है कि संपूर्ण भारतीयों का देश के बारे में, उसके इतिहास और बहुलतावादी संस्कृति के बारे में सांसारिक दृष्टिकोण सांझा नहीं है। मदरसों में शिक्षा ग्रहण किए हुए लोग शेष आकांक्षाओं से अपनी पहचान करने में कठिनाई का सामना करते हैं, इस प्रकार वे उस मानसिकता के शिकार हो जाते हैं जो एक एकाकी व असुरक्षित महसूस करने वाले समुदाय के लिए स्वाभाविक है।

उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भारतीय राजनीति में पंथनिरपेक्षता बनाम साम्प्रदायिकता के सम्भाषणों से बदलाव एक ऐसे एजेंडे की ओर होगा जिसमें सभी के लिए विकास पर एकसमान रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता हो।

उदाहरण के लिए, केरल में कांग्रेसनीत सरकार द्वारा पीडीपी नेता अब्दुल नसीर मदनी को अभियोजित करने से इनकार किया जाना, जबकि उन पर राज्य पुलिस द्वारा 2005 में तमिलनाडु बस अग्निकांड में शामिल होने का आरोप लगाया गया, एक और उदाहरण है जो कांग्रेस की छद्म धर्मनिरपेक्षता की प्रवृत्ति को परिलक्षित करता है। बाद में उन्हीं मदनी की बंगलौर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में बम विस्फोट की साजिश में संलिप्तता पायी गयी। पिछले वर्ष केरल में सत्तासीन कांग्रेसनीत सरकार द्वारा हर तरह की बाधाएं पैदा किए जाने के बावजूद कर्नाटक में सत्तासीन पूर्व भाजपानीत सरकार पर पीडीपी नेता को गिरतार करने की जिम्मेदारी छोड़ दी गई थी। एक अतिवादी से ऐसा बर्ताव करने के बजाए, वह जिस लायक है, करल सरकार यह सुनिश्चित करने का काम कर रही है कि जेल में मदनी कुशलतापूर्वक रहें, और वह कर्नाटक सरकार के काम में दखलंदाजी करती है। उत्तर प्रदेश में हुए पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान, कांग्रेसी नेतागण ने मुसलमानों के लिए आरक्षण प्रतिशत बढ़ाए जाने के वादे के अनुरूप परस्पर प्रतिस्पर्धा करते नजर आए। लेकिन अंत में तुष्टीकरण के खेल में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को पछाड़ दिया। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि समाजवादी पार्टी सरकार तब से सिलसिलेवार बम धमाकों को अंजाम देने के आरोपियों को रिहा करना चाहती है। अच्छा हुआ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दखल देकर आरोपियों को रिहा करने पर रोक लगा दी।

केरल में, मुस्लिम लीग संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार का हिस्सा है, उसे अत्यंधिक प्रतिनिधित्व मिला है और वह एक शीर्ष कांग्रेसी नेता को सरकार में पद पाने से इसलिए रोक देती है क्योंकि वो हिंदू हैं और उन्हें दो अत्यंत महत्वपूर्ण हिंदू संगठनों का समर्थन रहा है।

आंध्र प्रदेश में, जबसे कांग्रेस 2004 में सत्ता में आयी, वहां पर मुसलमान समुदाय को विशेष लाभ पहुंचाने के बारंबार प्रयास किए गए, मगर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने उन प्रयासों को नकार दिया।

किसी भी राष्ट्र में, विवाह, परिवार समेत व्यक्तिगत आचरण कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। यहां ऐसे पंथनिरपेक्षतावादी हैं जो एक समुदाय विशेष के लोगों पर इन कानूनों को लागू करने से रोक रहे हैं, इस तरह जनसांकिकीय पथांतरण एवं सामाजिक असंतोष की आधारशिला रख रहे हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी पत्नी रखने के लिए उस धर्म में अंतरण का दावा करते हैं, जो कि विवाह पर सामान्य कानून गवारा नहीं करता।

असम में, बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ जारी है और यह राज्य की कांग्रेसनीत सरकार की नाक के नीचे होता है क्योंकि अवैध प्रवासियों की पहचान किए जाने व वापस भेजे जाने सम्बंधी कानून केवल उल्लंघन करने के लिए बने हैं। कांग्रेस ने पंथनिरपेक्षता को नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत जोड़ने में आपातकाल के दौरान सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन पंथनिरपेक्षतावाद को परिभाषित नहीं किया गया है, जिसके चलते कांग्रेस व अन्य दल अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप उसका अर्थ लगा लेते हैं। अब इस विचार को प्रभावशाली ढंग से दरकिनार कर दिया गया है जिसे अंतर्गत सभी भारतीयों को सार्वजनिक लाभ तक भेदभाव रहित पहुंच का अधिकार है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के पक्ष में काम करने हेतु भेदभाव करते समय, विधि के समक्ष समानता का संवैधानिक मूल का सम्मान करना छद्म धर्मनिपेक्षतावादियों की निगाह में साम्प्रदायिकता है और जब सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं की बात आती है तो उसे पंथनिरपेक्षता मान लिया जाता है।

उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भारतीय राजनीति में पंथनिरपेक्षता बनाम साम्प्रदायिकता के सम्भाषणों से बदलाव एक ऐसे एजेंडे की ओर होगा जिसमें सभी के लिए विकास पर एकसमान रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता हो।■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं)

(पायनियर से साभार)

बना रहना चाहता है 'पिंजरे में बन्द तोता' संप्रग का सहयोगी

✍ अम्बा चरण वशिष्ठ

चाहे आप केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को उच्चतम न्यायालय के शब्दों में ''पिंजरे में बन्द तोता'' कहें या विपक्ष, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की भाषा में इसे कांग्रेस ब्यूरो आफ इन्वैस्टीगेशन, पर यह एजेंसी भाषा तो वही बोलती है जो सत्ताधारी दल उसे पढ़ाता है और वही करती है जो उसे सिखाया जाता है।

यदि आज कांग्रेस सरकारी तन्त्र का दुरुपयोग अपने विरोधियों के दमन के लिये कर रही है तो इसका कारण यह है कि 15 अगस्त 1947 को राज तो बदला पर निजाम नहीं बदला। गोरे तो गये पर प्रशासनतन्त्र व उसकी मानसिकता वही रही। कांग्रेस भी उसी दमनकारी नीतियों पर चलने लगी जो अंग्रेज अपना राज बनाये रखने के लिये बरतते थे। जो लाठी व गोली अंग्रेज चलाते थे वह स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी चलती रही। जो जुल्म अंग्रेज आजादी के दीवानों पर ढाते थे वही ढाने लगे जनतान्त्रिक शासक अपनी गद्दी बचाने व मनमानी चलाने के लिये। यदि अंग्रेजों के समय व आज के समय के पुलिस की लाठी-गोली के चित्र देखे जायें तो कोई विशेष अन्तर नहीं दिख पाता। दो वर्ष पूर्व बाबा रामदेव के समर्थकों पर जो बर्बरता मनमोहन सरकार ने दिल्ली के रामलीला मैदान में की, उससे तो अंग्रेजों के शासन की ही पुनरावृत्ति लगती थी। महिलायें और बच्चे भी इन जुल्मों से अछूते नहीं रहे।

वर्तमान मनमोहन सरकार के कार्यकाल में प्रशासन के सभी अंग व तन्त्र पुलिस, सरकारी अपराध जांच एजेन्सियां, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, खुफिया तन्त्र, और यहां तक कि राष्ट्रीय जांच एजेन्सी भी अपनी सारी शक्ति व ध्यान केवल एक ही लक्ष्य पर केन्द्रित किये बैठी हैं कि किस प्रकार शासक दल के हितों को बढ़ावा व संरक्षण दिया जाये, उसके चेहरे के काले धब्बों को छुपाया जाये, और दूसरी ओर उसके विरोधी दलों व व्यक्तियों को किस प्रकार प्रताड़ित किया जाये ताकि वह शासक दल के संकीर्ण राजनीतिक व चुनावी हितों की प्राप्ति व पूर्ति में बाधक न हो सके चाहे देश को उसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। हालात तो यहां तक पहुंच चुके हैं कि अब तो शासक दल अपने राजनीतिक व चुनावी हितों को राष्ट्रीय हित बता रहे हैं और जो उनके मनसूबों में रोड़ा बनते हैं उन्हें राष्ट्रद्रोही बताने तक में गुरेज नहीं करते।

संरक्षण के वरदहस्त का ही कमाल है कि दिनोंदिन सरकार तथा मन्त्रिमण्डलों में अपराध व भ्रष्टाचार की घटनायें आम होने लगी हैं। कानून के हाथ छोटे पड़ने लगे हैं जब भ्रष्टाचारी या अपराधी कोई मन्त्री या शासकदल से सम्बन्धित निकलता है और यही हाथ लम्बे हो जाते हैं जब ऐसा ही गलत काम विपक्ष का कोई व्यक्ति कर बैठता है। तब शासनतन्त्र अधिक सक्रिय, निर्दयी और क्रूर हो

संरक्षण के वरदहस्त का ही कमाल है कि दिनोंदिन सरकार तथा मन्त्रिमण्डलों में अपराध व भ्रष्टाचार की घटनायें आम होने लगी हैं। कानून के हाथ छोटे पड़ने लगे हैं जब भ्रष्टाचारी या अपराधी कोई मन्त्री या शासकदल से सम्बन्धित निकलता है और यही हाथ लम्बे हो जाते हैं जब ऐसा ही गलत काम विपक्ष का कोई व्यक्ति कर बैठता है। तब शासनतन्त्र अधिक सक्रिय, निर्दयी और क्रूर हो उठता है।

उठता है।

आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविन्द केजरीवाल ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा पर लगभग एक ही प्रकार के आरोप लगाये थे। वाड्रा मामले में यह इसलिये और भी गम्भीर हो जाते हैं क्योंकि इनमें कांग्रेस शासित प्रदेशों ने उन पर विशेष कृपा भी की थी। वाड्रा के मामले में तो मनमोहन सरकार व कांग्रेस ने कोई जांच करने का कष्ट उठाये बगैर ही तुरन्त उसी क्षण आरोपों को झूठा, बेबुनियाद और गैरजिम्मेदाराना करार दे दिया। प्रधान मन्त्री कार्यालय ने इन आरोपों पर किसी प्रकार जांच करवाये जाने की सम्भावना को भी इस तर्क पर नकार दिया कि ये आरोप ''दो निजी प्रतिष्ठानों के बीच व्यावसायिक सम्बन्धों'' के मामले बनते हैं। प्रधान मन्त्री कार्यालय ने इस बारे कोई सूचना देने से भी इंकार कर दिया।

पर श्री गडकरी का मामला भी तो बिलकुल वैसा ही था। फिर भी केन्द्रीय मन्त्री व कांग्रेस के नेता उनके त्यागपत्र की मांग करने लगे। 23 जनवरी को जब श्री गडकरी अपने दोबारा चुनाव के लिये अपना नामांकन भरने वाले थे तो ठीक एक दिन पहले आयकर विभाग ने उनके प्रतिष्ठानों पर छापे मार दिये। उनके विरुद्ध जांच का क्या बना, तब से अब तक कोई सूचना नहीं है। साप्ताहिक 'संडे गार्डियन' के अनुसार सरकार श्री गडकरी के विरुद्ध कोई भी ठोस सबूत प्राप्त करने में विफल रही है।

वास्तव में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने तो कांग्रेस के बचाव का वकील बनकर उन्हें बचाने व विरोधी दलों के लिये निर्दयी कोतवाल बनकर उन्हें फंसाने का सबूत देने में दिन-रात एक कर रखे हैं ताकि सत्ता पक्ष के संलिप्त लोगों का बचाव कर उन्हें निर्दोष साबित किया जाये और निर्दोष विरोधियों को फंसाने में कोई कसर न रह जाये।

वास्तव में केन्द्रिय जांच ब्यूरो ने तो कांग्रेस के बचाव का वकील व विरोधी दलों के लिये निर्दयी कोतवाल होने के सबूत देने में दिन-रात एक कर रखे हैं ताकि सत्ता पक्ष के संलिप्त लोगों का बचाव कर उन्हें निर्दोष साबित किया जाये और निर्दोष विरोधियों को फंसाने में कोई कसर न रह जाये।

1984 के सिख-विरोधी दंगों व 2002 के गुजरात दंगों पर सीबीआई का दोहरा मापदंड सर्वविदित ही है। जहां यह 1984 के दंगों में नामित कांग्रेसी नेताओं को बचाने में जुटी है वहीं गुजरात के दंगों में भाजपा नेताओं को फंसाने में उसने कोई कसर नहीं रखी है। 2009 लोक सभा चुनाव की पूर्व संध्या पर उसने कांग्रेसी नेताओं सज्जन कुमार व जगदीश टाइटलर के विरुद्ध दंगों में संलिप्त होने के आपराधिक मामले को बन्द करने का फैसला कर लिया पर माननीय अदालत ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। जब सज्जन कुमार को अदालत ने बरी कर दिया तो उस फैसले के विरुद्ध अपील दायर करने में उसे दो मास लग गये। श्री टाइटलर के विरुद्ध मामला अदालत के आदेश पर दोबारा खोला जा रहा है।

दूसरी ओर गुजरात में तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो और उसके माध्यम से मनमोहन सरकार की सारी शक्ति केवल एक बिन्दु पर केन्द्रित है कि इशरत जहां की तथाकथित फर्जी मुठभेड़ के मामले में किस प्रकार जैसे-तैसे भी प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी व अन्य भाजपा नेताओं को फंसाया जाये।

समाचार माध्यमों के अनुसार ब्यूरो ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के निजी सचिव श्री वी जार्ज के विरुद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित कर लेने के आपराधिक मामले को बन्द करने का निर्णय लिया है। बहाना यह है कि उसके विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पा रहे। साक्ष्य जुटाने का उत्तरदायित्व ब्यूरो का है या कि आम जनता या अपराधी का?

आय से अधिक सम्पत्ति जुटाने के ऐसे ही मामले पिछले 9 वर्ष से लम्बित पड़े हैं उत्तर प्रदेश के दो पूर्व मुख्य मन्त्रियों सुश्री मायावती व श्री मुलायम सिंह यादव के विरूद्ध। जैसे यह दोनों महानुभाव मनमोहन सरकार के प्रति अपना पैंतरा बदलते रहते हैं उनके रुख के अनुसार उसी प्रकार ब्यूरो भी अदालत में अपना रुख बदलता रहता है क्योंकि उसे तो वही करना है जो कांग्रेस चाहती है और ऐसा कुछ नहीं करना कि ये दोनों महानुभाव नाराज हो उठें और मनमोहन सरकार ही चलती बने। वास्तव में मनमोहन सरकार की अपनी टांगें तो हैं ही नहीं। वह तो मात्र सपा और बसपा की बैसाखियों पर टिकी हुई है।

इसी प्रकार कुछ वर्ष पूर्व श्री लालू प्रसाद यादव व उनकी पत्नी के विरुद्ध भी आय से अधिक सम्पत्ति जुटा लेने के आपराधिक मामले में यादव दम्पत्ति बरी हो गये। यह ब्यूरो की ही मेहरबानी थी कि उसने निचली अदालत के निर्णय के विरुद्ध बड़ी अदालत में अपील दाखिल नहीं की। सभी जानते हैं कि कांग्रेस को तो एक-एक सांसद के समर्थन की आवश्यकता है। इसलिये वह लालूजी को कैसे नाराज कर सकती

है?

पिछले लगभग 15 वर्ष से श्री लालू प्रसाद के विरुद्ध चारा घोटाले में संलिप्त होने के आपराधिक मामले में मुकद्दमा चल रहा है। इस बारे अनेक मामलों में तो निर्णय सुना दिया गया और कई अधिकारियों को सजा भी हो गई पर लालूजी के मामले में कुछ नहीं हो रहा। अब जब कि अन्त में अदालत ने अपना निर्णय सुनाने की तिथि निर्धारित कर दी तो पता नहीं उन्हें क्या आभास हो गया कि उन्हों ने उच्चतम न्यायालय में जाकर फैसला देने पर ही रोक लगवा दी। अब आगे का मामला भी सीबीआई के रहमोकरम पर ही निर्भर करेगा।

2जी स्पैक्ट्रम, राष्ट्रमण्डल खेल, कोलगेट जैसे अनेक घोटालों में सीबीआई का ढुलमुल रवैय्या इसी बात का द्योतक है कि वह सत्ता में बैठे अपराधियों को सजा दिलाने के लिये कितनी उतावली है। यदि थोड़ी बहुत चुस्ती दिखानी भी पड़ी है तो केवल तब जब अदालत का डण्डा सिर पर लटक जाता है।

नवीनतम है रेलगेट जिस कारण तत्कालीन रेल मन्त्री श्री पवन बंसल को त्यागपत्र देना पड़ा था। सीबीआई उन पर इतनी मेहरबान हो गई कि अपराधी बनाने की बजाय उन्हें अपने भांजे के विरुद्ध गवाह बना दिया गया। एक व्यक्ति ने ठीक ही कहा कि आज के जमाने में जब कोई व्यक्ति किसी को चाय का एक कप भी नहीं पिलाना चाहता जब तक कि उसे उस से किसी लाभ की उम्मीद न ही, सीबीआई रेलवे के एक महाप्रबन्धक को इतना मूर्ख समझ बैठी है कि वह बंसल के भांजे से 10 करोड़ घूस का सौदा कर बैठेगा और 2 करोड़ पहले ही दे देगा जब तक कि उसी तसल्ली न हो जाये कि उन का भांजा उसका मनचाहा काम कर देगा।

वास्तव में सीबीआई तो कांग्रेस के लिये ''सैंय्या भये कोतवाल तो डर काहे का'' मुहावरे को ही चरितार्थ कर रही है। ब्यूरो की चाल व चरित्र भी भाजपा के इस आरोप को ही सिद्ध कर रहा है कि सीबीआई ही वास्तव में कांग्रेस का सब से बड़ा राजनैतिक सहयोगी है जो उसकी सरकार को बचा रहा है।

अब जब कि उच्चतम न्यायालय ने संप्रग सरकार को आदेश दिया है कि वह कोई प्रस्ताव लाये जिससे कि ''पिंजरे का तोता'' स्वतन्त्र उड़ान ले सके तो कांग्रेस तोते को खुला नहीं छोड़ना चाहती। अपितु उसे पिंजरे से निकाल कर उस एक कमरे में ही उड़ने की आजादी देना चाहती है जिस में कोई खिड़की न हो और एक मात्र दरवाजे पर उसका कड़ा पहरा हो।

कहते है कि पिंजरे के तोते को यदि आजाद कर दिया जाये तो स्वतन्त्र विचरने वाले तोते उसे अपने साथ नहीं मिलाते। इसी डर से लगता है कि सीबीआई का तोता भी स्वतन्त्रता से गुरेज कर रहा है। उसने भी अब पिंजरे में ही बने रहने की अपील कर दी है। ■

(लेखक भाजपा साहित्य एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक हैं)

आंध्र प्रदेश भाजपा कार्यसमिति बैठक सम्पन्न

भारतीय जनता पार्टी, आंध्र प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 1 एवं 2 जुलाई 2013 को तिरूपति में संपन्न हुई। इस बैठक में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी श्री प्रभात झा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बंडारू दत्तात्रेय, राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल, राष्ट्रीय महामंत्री श्री मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन), राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती निर्मला सीतारमन एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री जी. किशन रेड्डी सहित प्रदेश पदाधिकारी व कार्यसमिति के सदस्य उपस्थित थे। ■

अर्थव्यवस्था की डूबती नाव

✍ लार्ड मेघनाद देसाई

बढ़ती महंगाई को कम करने और आर्थिक विकास को गति देने के मोर्चे पर जुटी संप्रग सरकार अपने तमाम प्रयासों के बावजूद देशी-विदेशी निवेशकों का भरोसा जीत पाने में विफल रही है, जिसका नतीजा डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत गिरने के रूप में हमारे सामने है। विदेशी निवेशक जहां भारत में धन निवेश करने के प्रति आशंकित हैं वहीं देसी निवेशकों को भी भारत से ज्यादा विदेश में निवेश करना फायदेमंद नजर आ रहा है। इतना ही नहीं अनिश्चित वैश्विक माहौल में हमारा निर्यात जहां लगातार घट रहा है वहीं सरकार की अदूरदर्शी नीतियों के कारण विभिन्न मदों में आयात का बोझ बढ़ रहा है, इस सबका सम्मिलित प्रभाव बढ़ते व्यापार घाटे के रूप में सामने है। अपनी गलत आर्थिक और राजनीतिक नीतियों के कारण सरकार आज महंगाई के दुष्चक्र में फंसी नजर आ रही है। चालू खाते के बढ़ते घाटे और बढ़ते राजकोषीय बोझ के कारण आर्थिक प्रबंधन चरमराया हुआ है, जिस कारण रुपया दिनोंदिन गिरने का नया रिकॉर्ड बना रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान में हमारी सात माह की आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाने की स्थिति में है।

जाहिर है सरकार अब हर तरफ से खुद को संकट में पा रही है और अर्थव्यवस्था हिचकोले लेती नजर आने लगी है। इस स्थिति में सरकार के पास करने के लिए अब जो बचा है वह यही कि वह विदेशी निवेशकों को किसी तरह भरोसा दिलाए कि सरकार आर्थिक

बढ़ती महंगाई को कम करने और आर्थिक विकास को गति देने के मोर्चे पर जुटी संप्रग सरकार अपने तमाम प्रयासों के बावजूद देशी-विदेशी निवेशकों का भरोसा जीत पाने में विफल रही है, जिसका नतीजा डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत गिरने के रूप में हमारे सामने है। विदेशी निवेशक जहां भारत में धन निवेश करने के प्रति आशंकित हैं वहीं देसी निवेशकों को भी भारत से ज्यादा विदेश में निवेश करना फायदेमंद नजर आ रहा है।

सुधार के काम को छोड़ेगी नहीं और इस दिशा में वह तेजी से सक्रिय होगी। आगामी आम चुनावों को देखते हुए निवेशक वर्तमान सरकार पर बहुत भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें केंद्र में बनने वाली अगली सरकार का इंतजार है। आर्थिक हालात को पटरी पर लाने के लिए सरकार को कड़े और नीतिगत फैसले लेने होंगे और आगामी चुनावों को देखते हुए इसकी संभावना बेहद कम है। यदि ऐसा कुछ फैसला लिया भी जाता है तो इसके परिणाम आने में समय लगेगा। कहने का आशय यही है कि किसी भी सूरत में सरकार को राहत नहीं मिलने वाली और न ही निवेशक इस सरकार पर फिलहाल भरोसा करने वाले। यही कारण है कि विदेशी संस्थागत निवेशक भारत से दूर जा रहे हैं और अपना पैसा वापस खींच रहे हैं। सरकार अनिश्चितता के इस माहौल में जैसे-तैसे निवेशकों को भरोसा दिलाना चाहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए सरकार कुछ क्षेत्रों में एफडीआइ यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने फिलहाल टेलीकॉम में शत-प्रतिशत एफडीआइ को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। वहीं देसी उद्योगपतियों के हित में गैस, कोयला आदि के दामों में वृद्धि करने का निर्णय भी लिया।

यदि सरकार के हालिया निर्णयों पर विचार किया जाए तो हम पाते हैं कि औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा की बढ़ती मांग और उत्पादन में असंतुलन कम करने के लिए सरकार निजी उद्यमियों पर निर्भरता की नीति पर चल रही है। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ऐसा करते समय सरकार को चाहिए कि वह मूल्य नियंत्रण का कोई तंत्र विकसित करे। इस दिशा में सरकार के पास अभी कोई नीति नहीं है। उद्यमियों के दबाव में निजी क्षेत्र के हित के नाम पर प्राकृतिक गैस के दाम में लगभग दोगुने की वृद्धि की गई और कोयले के दाम भी बढ़ाए गए, लेकिन ऐसा करते समय सरकार भूल गई कि इससे न केवल औद्योगिक उत्पादन महंगा होगा और महंगाई बढ़ेगी, बल्कि व्यापार घाटा भी बढ़ेगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि निजी कंपनियों से बड़ी मात्रा में सार्वजनिक कंपनियां प्राकृतिक गैस और कोयला खरीदती हैं, जाहिर है कि बढ़े दाम का दबाव इन कंपनियों के बजट पर पड़ेगा जिससे सरकारी घाटा बढ़ेगा। घरेलू उद्योगों और तापीय विद्युत परियोजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर

विदेशों से अपेक्षाकृत महंगा कोयला आयात करना पड़ रहा है। इसके दबाव से बचने के लिए जरूरी है कि सरकार जल विद्युत परियोजनाओं, सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा की संभावनाओं का अधिकाधिक दोहन करे ताकि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों को घरेलू संसाधनों से पूरा कर सके, लेकिन इसके लिए सरकार के पास कोई दीर्घकालिक नीति नहीं है।

सरकार इसके विपरीत अमेरिकी दबाव में ईरान से तेल का आयात घटा रही है और गैस व कोयले पर निर्भरता बढ़ा रही है। ऐसे में गैस और कोयले के बढ़े दाम से कुछ निजी उद्योगपतियों को तो लाभ होगा, जबकि दूसरे उद्योगों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और राजकोष पर भी दबाव बढ़ेगा। इसका विपरीत प्रभाव पुन: महंगाई बढ़ने के रूप में सामने आएगा। यही नहीं घरेलू मांग घटेगी तथा निर्यात प्रभावित होगा। हालांकि रुपये की कीमत में गिरावट से उम्मीद की जा रही है कि निर्यात बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था की हालत सुधरेगी, लेकिन विदेशी व्यापार का पूरा हिसाब किताब लगाया जाए तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। बेहतर यही होगा कि ऊर्जा कीमतों में वृद्धि का फैसला सरकार खुद करने के बजाय किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दे ताकि किसी समूह विशेष के दबाव में आकर देश के लिए अहितकर निर्णय नहीं हों। अभी ऐसा लगता है कि सरकार उद्योगपतियों के आगे नतमस्तक है और वह देश के दूरगामी हितों के संदर्भ में सही निर्णय ले पाने में सक्षम नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह ऐसे निर्णय ले, जिससे आम आदमी पर महंगाई का बोझ कम हो और व्यापार असंतुलन समेत राजकोष पर बढ़ता दबाव घटे। इसके लिए तत्काल काम करने की आवश्यकता है अन्यथा सरकार न तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकेगी और न ही अपनी चुनावी नैया पार लगा सकेगी।■ *(दैनिक जागरण से साभार)*

पृष्ठ 13 का शेष...

आवश्यक है। अभी हाल में ही एक रिटायर्ड जज को श्रीमती सुषमा स्वराज और मेरी अपनी सहमति न होने पर भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बना दिया गया। जज के रूप में उन्होंने जिस प्रकार की भूमिका निभाई थी, उसे देखते हुए सेवानिवृत्ति के बाद उनकी नियुक्ति न्यायसंगत नहीं थी। परन्तु सरकार तो लगता है कि उन्हें नियुक्त करने पर तुली हुई थी। रेल मंत्री के रूप में श्री लालू प्रसाद यादव ने रेलवे एक्ट के अधीन साबरमती एक्सप्रेस कोच में वास्तव में हुई एक घटना के एक वर्ष बाद जांच करने के लिए एक रिटायर्ड जज को नियुक्त कर दिया था। इस रिटायर्ड जज ने आरोपियों की दोषसिद्धि की बात को एक तरफ रख दिया और ऐसी रिपोर्ट पेश की कि किस प्रकार से कारसेवक गाड़ी के अंदर से उसे जला सकते हैं। एक और रिटायर्ड जज को भारत और जम्मू-काश्मीर राज्य के बीच संवैधानिक सम्बन्धों पर प्रधानमंत्री के वर्किंग ग्रुप की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया। मैं इस वर्किंग ग्रुप का सदस्य था। वर्किंग ग्रुप के नाम पर एक रिपोर्ट पेश की गई जबकि इसकी एक भी बैठक कभी नहीं हुई। जब रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो जज का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिससे ऐसा कुछ लगता था कि इस रिपोर्ट को उन्होंने स्वयं लिखा है। हम उस विद्वान जज को कभी नहीं भुला सकते जिन्होंने 6 दिसम्बर 1992 के ढांचे को विध्वंस करने के आरोप के बारे में जांच आयोग की अध्यक्षता की थी। आयोग ने अपना कार्यकाल बढ़ाते-बढ़ाते 17 वर्ष तक कार्य कर अपनी नौकरी बनाए रखी। उनकी पेश की गई रिपोर्ट कार्यान्वयन-योग्य ही नहीं थी और इसका कार्यान्वयन नहीं हुआ। इस तरह की सूची का कहीं कोई अन्त नहीं है। सरकार द्वारा इस प्रकार के बेजवाबदेही वाले रिटायर्ड जजों की संस्थागत तंत्र खड़ा करने से, जिसके लिए सीबीआई जवाबदेही होगी, परिणाम कुछ नहीं निकलेगा और इसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि सरकार स्वयं को दृश्यावली से ओझल कर सीबीआई पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगी और बस एक प्राक्सी इंस्टीट्यूशन खड़ा कर देगी जो सरकार की तरफ से काम करेगा।

यूपीए ने सीबीआई का दुरूपयोग कर इसकी उम्र बढ़ा दी है। सपा और बसपा के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में सीबीआई की भूमिका से यही सुनिश्चित हुआ है कि ये पार्टियां निरन्तर यूपीए को समर्थन देने पर विवश हैं। गुजरात और राजस्थान में भाजपा नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करने में सीबीआई की भूमिका ने दिखा दिया है कि सीबीआई सत्ता में बैठी पार्टी के हुकुम पर चलकर उनका हित साधती रहती है। जीओएम पर यूनियन केबिनेट का हाल का निर्णय मात्र धोखा है। इससे राजनैतिक सरकार को हटाने और इसकी बजाय प्राक्सी इंस्टीट्यूशन खड़ा करने का भ्रम पैदा कर दिया है। सरकार का फैसला वर्तमान समस्या से कहीं ज्यादह गया-गुजरा है। बेहतर होगा कि सरकार प्रवर समिति की सिफारिशों तथा 31 जनवरी 2013 के केबिनेट निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे और साथ ही अन्य राजनैतिक दलों के उन सुझावों को भी रखे जो सीबीआई को राजनैतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए इन्होंने कहे हैं। ■

(लेखक राज्य सभा में विपक्ष के नेता हैं)

महान भारत के लिए नारी शक्ति का सम्मान जरूरी : राजनाथ सिंह

नारी शक्ति को सम्मान दिये बिना भारत को महान नहीं बनाया जा सकता। उक्त बातें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने 29 जून 2013 को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की गाजियाबाद में हो रही राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक में कही।

श्री सिंह ने कहा कि आज देश की राजधानी में ही महिलाओं के प्रति जघन्य अपराध हो रहे है। इससे बड़ा कलंक और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में भी कमोवेश यही स्थिति है। नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। देश की संस्कृति बिगड़ रही है।

श्री सिंह ने कहा कि देश में आज सांस्कृतिक पुनर्जागरण की घोर आवश्यकता है। इसके साथ शैक्षिक नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता है जो भाजपा ही पूरा कर सकती है। वर्तमान सरकार से इसकी अपेक्षा नही की जा सकती है क्योंकि नीतियां बनाने वाले व स्वयं पी.एम.ओ. भ्रष्टाचार व घोटालों में आरोपित है। सी.बी.आई. उसके अधिकारियों से पूछताछ कर रही है।

श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है जबकि कांग्रेस ने 100 दिनों में मंहगाई घटाने का वादा किया था। कांग्रेस की गलत आर्थिक नीतियों व नियोजन के कारण महंगाई बढ़ रही है। आज लोग अटल जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार को याद करते है जिसने महंगाई पर काबू पाया था। रुपये का अवमूल्यन हो रहा है देश के हालात बिगड़े हुये है। निवेशक डरे हुए है। माओवाद, नक्सलवाद तथा आतंकवाद से सारा देश प्रभावित हो रहा है।

श्री सिंह ने महिलाओं का आह्वान किया कि ऐसी निष्क्रिय सरकार जानी चाहिये। भाजपा महिलाओं को 33प्रतिशत आरक्षण दिलाएगी। भाजपा ही भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बना सकती है। भाजपा ने इसी योजना को ध्यान में रखकर देश के सबसे अधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को चुनाव प्रचार अभियान समिति की बागडोर सौपी है। पोलिंग बूथ कमेटियों पर ध्यान देना आवश्यक है। कार्यकर्ता की छवि भी साफ सुथरी होनी चाहिये। बेहतर चरित्र और जनता के विश्वास के बल पर 2014 में सरकार बनाने मे कामयाब होंगे।

महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सरोज पांडे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सर्वविदित है कि देश में सरकार बनाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उ0प्र0 की संस्कृति भी समृद्ध है और महिला मोर्चे की पहली राष्ट्रीय कार्यसमिति उ0प्र0 में होना सौभाग्य की बात है। श्रीमती पांडे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को विश्वास दिलाया कि आगामी लोकसभा के चुनाव में भाजपा को विजय दिलाने में महिलाओं की उल्लेखनीय भूमिका रहेगी।

इससे पूर्व उत्तराखण्ड की त्रासदी में मारे गये लोगों के तथा सैनिकों के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन रखा गया। कार्यक्रम में देश भर से आई महिलाओं ने प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से सुधा यादव, आनन्दी बेन, वासु बेन, संयुक्ता भाटिया, दर्शना, विजया कान्ता जानावड़ी, आशा शर्मा, कमलावती सिंह, तेलूराम कम्बोज, भूपेन्द्र सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में महिला प्रतिनिधि शामिल थीं।■

नया राजस्थान बनाएंगे, नई व्यवस्था लाएंगे

✍ वसुंधरा राजे

सुराज संकल्प यात्रा के चौथे चरण की शुरूआत करने से पूर्व डिग्गी स्थित भगवान श्री कल्याण जी महाराज के मंदिर में दर्शन करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं भगवान श्री कल्याणजी महाराज से राजस्थान की जनता की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हूं।

सुराज संकल्प यात्रा के दौरान मैंने

उदयपुर, कोटा, भरतपुर और अजमेर संभाग की यात्रा पूर्ण की है। यात्रा जिस रास्ते से भी गुजरी लोगों ने विशेषकर महिलाओं ने शिकायत की कि न पानी, न बिजली, हम कैसे जिएं? बात इन चारों संभागों की ही नहीं है अपितु पूरा प्रदेश बिजली, पानी के संकट से त्रस्त है। गांवों में बिजली की अघोषित कटौती से लोग परेशान हैं, वे कहते हैं कि यह सरकार पूरे साढ़े चार साल में बिजली, पानी जैसी मूलभूत जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाई तो इससे और क्या उम्मीद करें।

पूरे प्रदेश में पानी और बिजली का हाहाकार मचा हुआ है और सरकार को कोई चिंता नहीं है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर राजस्थान को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। पूर्व में जब हमारी सरकार थी तब अलग से घरेलू बिजली की लाईन खींचवाकर फीडर सुधार कार्यक्रम के तहत शहरों में ही नहीं गांवों में भी 22 घंटे बिजली दी थी। हमारी योजना, घरेलू बिजली 24 घंटे की थी। किंतु इसी बीच हमारी सरकार चली गई। आज प्रदेश में बिजली का संकट गहराया हुआ है। अघोषित कटौती ने प्रदेशवासियों का जीना दूभर कर दिया है। हमारा सपना है कि हम एक नया राजस्थान बनाएंगे और नई व्यवस्था लाएंगे। कांग्रेस तो झूठ के सहारे सत्ता में आती है, जबकि भाजपा वोटों की खातिर झूठ नहीं बोलती। हमारी सरकार, जनता की अपनी होगी। मूलभूत सुविधाएं ही हमारी सरकार की प्राथमिकता होंगी जिसमें अपना घर, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा पर पूरा फोकस होगा।

प्रदेश में जब हमारी सरकार थी, तो हमने 50 लाख महिलाओं के लिए भामाशाह योजना बनाई थी। जिसमें बीपीएल परिवारों के लिए 30 हजार रुपए का बीमा भी था। प्रत्येक महिला के खाते में प्रोत्साहन स्वरूप 1500 रुपए जमा होने थे, किंतु अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस सरकार ने आते ही यह योजना रोक दी जिससे 50 लाख महिलाएं, बैंक सुविधाओं से वंचित हो गई। यह योजना भारत में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में अनूठी थी।

आज चुनाव आते देखकर यह सरकार पैसा रेवड़ियों की तरह बांट रही है। किसानों को सही समय पर खाद-बीज और बिजली नहीं मिल रही है जिससे किसान परेशान हैं और जो खाद-बीज मिल भी रहा है तो वह नकली है। किसान अपना खून-पसीना एक करके फसल तैयार कर बाजार में बेचने जाता है तो उसे लागत भी नहीं मिलती है। ओलावृष्टि हो जाती तो उसे सरकार की घोषणा के बावजूद मुआवजा भी नहीं मिलता।

यह सरकार घोषणाएं तो करती है पर उन्हें पूरा नहीं करती। ऐसे हालात में राजस्थान का किसान खेत में मर रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है, किंतु उस किसान की इस सरकार को कोई चिंता नही। कांग्रेस सरकार किसी भी सूरत में पुन: सत्ता पाना चाहती है इसके लिए लोगों में योजनाओं के नाम पर पैसे बांटे जा रहे हैं, मैं तो कहती हूं कि यह पैसे आपका अपना पैसा है। इसे ले लो किंतु वोट सोच-समझकर दो।■

(लेखिका भाजपा, राजस्थान प्रदेश की अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में प्रदेश भर में गत तीन महीने से 'सुराज संकल्प यात्रा' चल रही है)

उच्च न्यायालय द्वारा धड़ाधड़ स्थानांतरणों पर रोक लगाना स्वागतयोग्य : धूमल

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष प्रो0 प्रेम कुमार धूमल ने माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा राजनैतिक आधार पर प्रदेशभर में हो रहे धड़ाधड़ स्थानांतरणों पर रोक लगाने के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत और सराहना की है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक निर्णय से भाजपा के इन आरोपों की पुष्टि होती है कि कांग्रेस सरकार राजनैतिक द्वेष और पूर्वाग्रह से पीड़ित होकर सत्तारूढ़ दल के छुटभैये नेताओं की अनुशंसाओं पर सरकारी कर्मचारियों के तबादले कर रही है।

राजनैतिक द्वेष व पूर्वाग्रह से पीड़ित होकर कर्मचारियों के तबादले न करें और इसके लिए अगर कोई नीति बनानी है तो प्रदेश सरकार मा0 उच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक निर्णय को मद्देनजर रखते हुए नई स्थानांतरण नीति बनाए और तब तक प्रदेशभर में कर्मचारियों के स्थानातंरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए।

प्रो0 धूमल ने कहा कि यह संयोग है कि उच्च न्यायालय ने जिस दिन यह ऐतिहासिक निर्णय दिया और इस संदर्भ में गंभीर संज्ञान लेते हुए कहा कि राजनैतिक व्यक्तियों की सिफारिश पर कर्मचारियों के तबादले नहीं होने चाहिए उसी दिन प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई स्थानांतरण नीति को स्वीकार किया और सरकार ने तबादलों पर राजनैतिक अनुशंसा को लेकर ठीक इसके विपरित निर्णय लिया। प्रो0 धूमल ने कहा कि कर्मचारियों का स्थानांतरण प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है परन्तु उसका आधार प्रशासनिक व लोकहित होना चाहिए न कि निराश, हताश व लोगों द्वारा नकारे जा चुके सत्ता दल के नेताओं की अनुशंसा होना चाहिए। इस तरह से कर्मचारियों का स्थानातंरण करना इनके मनोबल को गिराता है और विकास कार्यों को अवरूद्ध करता है।

प्रो0 धूमल ने कहा कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले एक सामान्य प्रक्रिया है और हर वर्ष मार्च और अप्रैल के महीने में प्रशासनिक आधार पर तबादलों की प्रक्रिया चलती है और यह सरकार का अधिकार भी है, परन्तु वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण को सरकार के मंत्रियों, पार्टी के नेताओं और पहुंच वाले दलालों ने इसे एक उद्योग में तबदील कर दिया है। मात्र 6 महीनों में हजारों तबादले वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली के प्रतीक हैं।

प्रो0 धूमल ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में कर्मचारियों को यथायोग्य सम्मान दिया गया था। कभी कर्मचारियों के नाजायज तबादले नहीं किए गए थे। यही वजह रही कि सरकारी कर्मचारियों ने प्रदेश के विकास के लिए दिन रात मेहनत की और जिसके कारण हिमाचल प्रदेश लगातार 4 वर्ष 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में देशभर में प्रथम रहा और पांच वर्षो के भाजपा सरकार के कार्यकाल में 80 से ज्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुए।

आज सत्ता प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस सरकार इन्हीं कर्मचारियों व अधिकारियों के उत्पीड़न में लगी हुई हैं। योग्य अधिकारियों व कर्मचारियों को पूर्वाग्रह के चलते स्थानांतरित किया जा रहा है और उनकी जगह रिटायर्ड व टायर्ड अधिकारियों व कर्मचारियों को नियुक्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदेशभर में विकास कार्यों को ग्रहण लग चुका है और प्रदेश का विकास थम गया है।

प्रो0 धूमल ने सरकार से आग्रह किया है कि वे राजनैतिक द्वेष व पूर्वाग्रह से पीड़ित होकर कर्मचारियों के तबादले न करें और इसके लिए अगर कोई नीति बनानी है तो प्रदेश सरकार मा0 उच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक निर्णय को मद्देनजर रखते हुए नई स्थानांतरण नीति बनाए और तब तक प्रदेशभर में कर्मचारियों के स्थानातंरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए। ■

भाजपा-हजकां ने चलाया 'घर-घर चलो अभियान'

भ्रष्टाचार पर विराम-कांग्रेस को विश्राम'' के उद्घोष के साथ भाजपा-हजकां गठबन्धन के हजारों कार्यकर्ताओं ने 1 जुलाई को यूपीए सरकार के मंहगाई, भ्रष्टाचार एवं महाघोटालों को लेकर 'घर-घर चलो अभियान' के तहत प्रदेश भर में व्यापक जनजागरण अभियान प्रारम्भ कर दिया है।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरकुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम एक जुलाई को प्रारम्भ होकर 31 जुलाई तक चलेगा। श्री यादव के अनुसार भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष प्रो. रामबिलास शर्मा ने कार्यक्रम प्रारम्भ करते हुए जिला महेन्द्रगढ़ के गांव नांगल सिरोही में कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि इस समय आम व्यक्ति देश व प्रदेश की कांग्रेस सरकारों से त्रस्त, दुखी व परेशान है। कमरतोड़ मंहगाई से आम व्यक्ति का जीना दुर्भर हो गया है। इस अवसर पर उनके साथ हजकां के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक नरेश यादव ने भी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया। श्री यादव ने बताया कि हजकां सुप्रीमों व सांसद कुलदीप बिश्नोई व भाजपा नेता व पूर्व गृहराज्य मंत्री आई. डी.स्वामी ने रोड़ धर्मशाला में गठबन्धन के कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के सांसद नवीन जिंदल से प्रधानमंत्री मनमोहन तक सभी कांग्रेंसी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए है। पेट्रोल व गैस की कीमतों में इजाफा करके आम व्यक्ति की कमर तोड़ दी है। प्रदेश भर में वातावरण गठबन्धन के अनुकूल है।

श्री यादव के अनुसार इसी कड़ी में हजकां के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद पं. रामजीलाल व भाजपा के प्रदेश महामंत्री मनीष ग्रोवर ने रोहतक के पहरावर गांव में गठबन्धन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ घर-घर जाकर यूपीए सरकार की जनविरोधी नीतियों से लोगो को अवगत कराया। वहीं हजकां की विधायक श्रीमती रेणुका विश्नोई व भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. कमल गुप्ता ने मंडी आदमपुर में कार्यक्रम की शुरूआत की। पूर्व सांसद चौ. रामचन्द्र बैन्दा व पूर्व विधायक चन्द्र भाटिया तथा हजकां के तेजपाल शर्मा ने फरीदाबाद के गांव मच्छगर, हजकां के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद जंगबीर व भाजपा नेता ऋषिप्रकाश शर्मा ने भिवानी शहर, हजकां के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद गुरदयाल सैनी व भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कृष्ण बेदी ने कुरूक्षेत्र के ज्योतिसर में कार्यक्रम के अन्तर्गत घर-घर जाकर अटल जी के शासन की उपलब्धियों व वर्तमान यूपीए सरकार की जनविरोधी नीतियों से आम लोगो को अवगत कराया।

प्रदेश प्रवक्ता के अनुसार इस दौरान आम लोगों ने गठबन्धन के प्रति अपना भरपूर सहयोग व समर्थन दिया। वहीं कार्यक्रम को लेकर गठबन्धन के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह, उमंग व उल्लास का वातावरण दिखाई दिया। उन्होने बताया कि जिला फतेहाबाद में भूना से हजकां के वरिष्ठ नेता चौ. दूड़ाराम व भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुभाष बराला, पानीपत के चुकलाना गांव में भारतीय किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष महीपाल ढांडा व हजकां के डी एन त्यागी, जिला गुडग़ांव में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव डा. सुधा यादव व प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री राव नरबीर ने गठबन्धन के सैकडों कार्यकर्तीओं के साथ अभियान की शुरूआत की। रेवाड़ी जिला के मोती चौक में हजकां के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक रघु यादव व भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश ग्रोवर, कैथल के गांव क्योंडक से हजकां के वरिष्ठ नेता बलकार सिंह व भाजपा के धर्मबीर डागर, सोनीपत में गोहाना के समता चौक से भाजपा उपाध्यक्ष राजीव जैन व हजकां के सुधा मलिक, जीन्द में हाट कालवा गांव में भाजपा के उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार गुर्जर व हजकां के पूर्व विधायक सुबे सिंह पूनियां, सिरसा में जनता धर्मशाला मार्केट से भाजपा सचिव के महावीर प्रसाद व हजकां के पूर्व मंत्री रामस्वरूप रामा, मेवात में नूहं से भाजपा के वरिष्ठ नेता भानीराम मंगला व हजकां के पूर्व विधायक सचदेव त्यागी, पलवल के बडौली गांव में भाजपा प्रवक्ता दीपक मंगला, मूलचन्द शर्मा व हजकां के शक्तिसिहं रावत, झज्जर में हजकां के पूर्व विधायक गणपत राम व भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश गोयल व दादरी के रामनगर गांव से हजकां के पूर्व विधायक धर्मपाल व जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक नरपेन्द्र सांगवान ने गठबन्धन के सैकड़ो कार्यकर्ताओं सहित घर-घर चलो अभियान की शुरूआत की। ■

आतंकी हमला : बोधगया में सिलसिलेवार बम ब्लास्ट, दहली बुद्धभूमि

बिहार के गया जिले के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में 7 जुलाई को हुए सिल-सिलेवार बम विस्फोटों से दहल उठा। बम विस्फोट में पवित्र बोधिवृक्ष के समीप साधना कर रहे एक तिब्बती लामा तेनजीन व म्यांमार के बौद्ध भिक्षु विलासागा घायल हो गए। जिन्हें इलाज के लिए गया के

मगध मेडिकल कालेज सह अस्पताल भेजा गया। मंदिर के बाहर लाल पैडस्टल पर पड़ा बौद्ध भिक्षु का खून शांति भूमि पर अशांति के हमले की कहानी बता रहा था। बोधिवृक्ष के नीचे रखी लकड़ी की बेंच के परचखे उड़ गए और उस पर रखा चीवर बोधिवृक्ष पर जा लटका। विस्फोट में वज्रासन की ओर चढ़ने वाली सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो गई।

महाबोधि मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के सचिव एन. दोरजे की मानें तो मंदिर परिसर में पहला विस्फोट बोधिवृक्ष के समीप हुआ। उसके बाद तारा देवी मंदिर, बटर लैंप हाउस और फिर रत्नगृह में कुछ मिनट के अंतराल पर चार विस्फोट हुए। उन्होंने कहा कि बोधिवृक्ष के समीप साधना कर रहे दो बौद्ध भिक्षु घायल हैं।■

केंद्र सरकार पर बरसे भाजपा अध्यक्ष

बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली केंद्र सरकार पर 9 जुलाई को जमकर बरसे।

श्री राजनाथ सिंह ने बोधगया में विस्फोट स्थलों का निरीक्षण और महाबोधि मंदिर के गर्भ गह में जाकर भगवान बुद्ध की पूजा-अर्चना करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि वह भाजपा की ओर से इस घटना की तीव्र भर्त्सना करते हैं और पूरे मामले की जांच की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि वह केंद्र सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह इस अंतरराष्ट्रीय बौद्ध केंद्र की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंधन करे।

श्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार को यहां हमले को लेकर आठ-नौ महीने खुफिया सूचना मिली थी, लेकिन जो खास खुफिया जानकारी मिलनी थी वह शायद न मिली हो। उन्होंने कहा कि यदि खुफिया सूचना मिली थी, तो उस स्थिति में, जो भी प्रमुख बौद्ध केंद्र हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था राज्य और केंद्र सरकार द्वारा की जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि कोई राज्य अकेले आतंकवाद और माओवाद से नहीं लड़ सकता। ऐसे में केंद्र की यह जिम्मेवारी बनती है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पूरी व्यवस्था करे। श्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद से निपटने के लिए देश में व्यापक कार्य योजना बनाए जाने की वकालत करते हुए कहा कि ऐसी मांग उनकी पार्टी की ओर से कई बार की जा चुकी है लेकिन केंद्र की संप्रग सरकार चुप्पी साधे हुए है। राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली ने आरोप लगाया कि केंद्र की कांग्रेस नीत संप्रग सरकार ने देश की सुरक्षा को वोट बैंक की राजनीति के साथ जाड़ रखा है, ऐसे में इस तरह के आतंकी हमले होते रहेंगे।

श्री जेटली और राज्यसभा में भाजपा के उपनेता श्री रविशंकर प्रसाद, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री नंदकिशोर यादव सहित पार्टी के अन्य नेताओं के साथ श्री राजनाथ सिंह ने गया जिला स्थित मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल जाकर बोधगया विस्फोट में घायल हुए दो बौद्ध भिक्षुओं से सभी मुलाकात की और उनके इलाज के बारे में जानकारी हासिल की। श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम चाहते हैं कि देश आगे बढ़े और आतंकवाद के खिलाफ एक स्वर में लड़े और बिहार सरकार को भी आगे आना चाहिए। ■

शहीद शिरोमणि चन्द्रशेखर आजाद

✍ विकास आनन्द

भारत माता करीब दौ सौ सालों से अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। फिरंगियों की बेड़ियों से मुक्ति दिलाने के लिए न जाने भारत माता के कितने वीर और राष्ट्रभक्त सपूत शहीद हो गए। उनमें से एक चन्द्रशेखर आजाद थे जिनके नाम से ब्रिटिश हुकूमत कांपती थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क (अब चन्द्रशेखर आजाद पार्क) में लहुलुहान पड़ा उनके मृत शरीर के पास जाने की किसी ब्रिटिश पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी।

इस देशभक्त वीर सपूत का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव (अलीराजपुर जिला) में हुआ था। वैसे इनके दादा-परदादा उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के रहने वाले थे।

चन्द्रशेखर आजाद का बचपन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भावरा गांव में ही व्यतीत हुआ। भील बालकों के साथ रहते-रहते चन्द्रशेखर आजाद ने बचपन में ही धनुष बाण चलाना सीख लिया था जोकि बाद में अंग्रेजों के साथ लड़ाई में काफी काम आया। चन्द्रशेखर आजाद की माता जगरानी देवी उन्हें संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी।

इसीलिए उन्हें संस्कृत सीखने के लिए काशी विद्यापीठ बनारस भेजा गया। दिसम्बर 1921 में जब गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरूआत की गई उस समय मात्र चौदह वर्ष के थे। इस छोटी सी आयु में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा और मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया तब मजिस्ट्रेट के पूछे जाने पर उन्होंने अपना नाम 'आजाद' और पिता का नाम 'स्वतंत्रता' बताया। यहीं से चन्द्रशेखर सीताराम तिवारी 'चन्द्रशेखर आजाद' हो गए। चन्द्रशेखर को पन्द्रह दिनों के कड़े कारावास की सजा प्रदान की गई।

महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस घटना ने चन्द्रशेखर आजाद को बहुत आहत किया। उन्होंने किसी भी तरह देश को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्रता दिलवाने का निश्चय किया। आजाद युवा क्रांतिकारी प्रनवेश चैटर्जी के

सम्पर्क में आये। उन्होंने आजाद को हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे क्रांतिकारी दल के संस्थापक रामप्रसाद बिस्मिल से मिलवाया। चन्द्रशेखर आजाद इस संस्था और बिस्मिल के समान स्वतंत्रता और बिना किसी भेदभाव के सभी को अधिकार जैसे विचारों से बहुत प्रभावित हुए और इस संस्था से जुड़ गए। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए चन्द्रशेखर आजाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर साण्डर्स की हत्या की थी।

अंग्रेजों द्वारा की जा रही निर्दयतापूर्ण व्यवहार ने चन्द्रशेखर आजाद को मानने के लिए बाध्य कर दिया कि संघर्ष की राह में हिंसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। जलियावालां बाग जैसे अमानवीय घटना, जिसमें हजारों निहत्थे और बेगुनाहों पर गोलियां बरसाई गई, ने चन्द्रशेखर आजाद को बहुत चोट पहुंचाई जिसके बाद उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से आजादी पाना ही अपना एक मात्र लक्ष्य बना लिया।

1924 में हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1925 में काकोरी कांड हुआ जिसके आरोप में अशफाक उल्ला खां, बिस्मिल समेत अन्य मुख्य क्रांतिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई जिसके बाद चंद्रशेखर ने इस संस्था का पुनर्गठन किया। भगवतीचरण वोहरा के संपर्क में आने के बाद चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के भी निकट आ गए थे। इसके बाद भगत सिंह के साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजी हुकूमत को ललकारने और भारत से खदेड़ने का हर संभव प्रयास किया।

1931 में फरवरी के अंतिम सप्ताह में चंद्रशेखर आजाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ एल्फ्रेड पार्क जाकर आगामी योजनाओं के विषय में बात ही कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हे घेर लिया। लेकिन उन्होंने बिना सोचे अपने जेब से पिस्तौल निकालकर गोलियां दागनी शुरू कर दी। दोनों ओर से गोलीबारी हुई।

लेकिन जब चंद्रशेखर के पास मात्र एक ही गोली शेष रह गई तो उन्हें पुलिस का सामना करना मुश्किल लगा। चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही यह प्रण किया था कि वह कभी भी जिंदा पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। इसी प्रण को निभाते हुए उन्होंने वह बची हुई गोली खुद को मार ली। आज के राष्ट्रभक्तों के लिए भारत मां के ऐसे वीर सपूत प्रेरणास्रोत हैं।■